page 1 and 8_page 1 Mar 25 final ds.qxd 11/30/2025 1:29 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 कठुआ विधायक ने विश्वविद्यालय अन्वेषण मेला 2025 का किया उद्घाटन

5 इंग्लैंड को रन चेंज के लिए तैयार रहना होगा: माइकल वान

8 कुदरत के दिये गये वरदानों में पेड़-पौधों का महत्वपूर्ण स्थान

मौसम जम्मू — न्यूनतम 9 — अधिकतम 21

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-293 | जम्मू तवी, रविवार 30 नवम्बर, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

'ऑपरेशन सिंदूर' ने सिविल-मिलिट्री के बीच असरदार तालमेल दिखाया : राजनाथ

मसूरी, 29 नवंबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने सिविल-मिलिट्री के बीच असरदार तालमेल दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी कैंपों पर हमलों से पड़ोसी देश घबरा गया।

न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर ज़रूरी जानकारी पहुंचाई और पूरे देश में लोगों का भरोसा बनाए रखा।

उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों पर संतुलित और बिना उकसावे वाले जवाब में हमले किए। उन्होंने आगे कहा, कार्रवाई से पड़ोसी देश घबरा गया। रक्षा मंत्री ने कहा, पड़ोसी देश

के बर्ताव की वजह से बॉर्डर पर तनाव था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने सही बातचीत और पूरे देश में मॉक ड्रिल को अंजाम देना पक्का किया। सिंह ने कहा कि यह घटना गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बीच कोऑर्डिनेशन के महत्व को दिखाती है और उन्होंने 2047 तक एक डेवलप्ड देश बनने के लक्ष्य को पाने के लिए इस कनेक्शन को और मज़बूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा सिविल सर्वेंट्स को नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा में अपने योगदान को पहचानना चाहिए और फ्रंट लाइन पर सैनिकों के सामने आने

ऑपरेशन सिंदूर सिविल-मिलिट्री फ्यूजन का शानदार उदाहरण है- राजनाथ

वाली अचानक और मुश्किल स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के मकसद से रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है और कहा कि सिविल सर्वेंट्स भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में सेंट्रल रोल निभाते हैं। यह बताते हुए कि भारत पिछले दशक में 11वीं से चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स अब उम्मीद करते हैं कि भारत अगले दो से तीन सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। उन्होंने युवा ऑफिसर्स को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया, साथ ही यह पक्का किया कि यह एक टूल बनी रहे, एंड नहीं। उन्होंने टेक्नोलॉजी-बेस्ड गवर्नेंस के उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेसलेस असेसमेंट सिस्टम जैसी स्कीम्स का ज़िक्र किया। सिंह ने रक्षा मंत्रालय की AI से चलने वाली SAMPUR-NA पहल का भी ज़िक्र किया, जो रक्षा खरीद और पेमेंट का एनालिसिस करती है। उन्होंने कहा कि ट्रेनी को नागरिकों से हमदर्दी और समझदारी से मिलना चाहिए, खासकर समाज के कमज़ोर तबके से, जिनके संघर्ष बड़े सामाजिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित होते हैं। उन्होंने सिविल सर्विसेज़ में महिलाओं के बढ़ते रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा जताया, और हाल के UPSC नतीजों का ज़िक्र किया, जिसमें महिलाओं ने टॉप पोजीशन हासिल कीं।

उपराज्यपाल ने रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को पक्का घर देने के मकसद से पुनर्वास परियोजनाओं की रखी नींव

रामबन, 29 नवंबर । जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को रामबन जिले का दौरा किया और बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को पक्का घर देने के मकसद से पुनर्वास परियोजनाओं की नींव रखी।

मीडिया से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने सभी हितधारकों की मदद से सरकारी नियमों के मुताबिक प्रभावित परिवारों को राहत और बचाव का काम दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि हम जानते हैं कि सिर्फ़ सरकारी मदद घरों को फिर से बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। एचआरडीएस संस्था के साथ साझेदारी में रामबन ज़िले के 189 परिवारों को अगले छह महीनों में तीन कमरों वाले घर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि घरों के साथ 15 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ चेक-अप और इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी जिससे परिवार सुरक्षित और इज्ज़तदार ज़िंदगी जी सकेंगे।

उन्होंने ज़िला प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि जो भी प्रभावित या गरीब परिवार शुरुआती सूची में छूट गए हों, उन्हें शामिल किया जाए। सिन्हा ने पुनर्वास की कोशिशों में मदद करने के लिए एचआरडीएस का शुक्रिया अदा किया।उपराज्यपाल ने कहा कि राजौरी और उधमपुर समेत दूसरे प्रभावित इलाकों में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में

प्रभावित परिवारों के लिए घरों को फिर से बनाना उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। सिन्हा ने कहा कि रामबन में आज की पहल एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित सभी परिवारों को सुरक्षित और पक्का घर मिले।

उन्होंने कहा कि प्रशासन पुनर्वास का काम अच्छे से पूरा करने और यह पक्का करने के लिए है कि सभी लाभार्थी सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकें।

पहले फ़ेज़ में, हाल की प्राकृतिक आपदाओं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना उकसावे के पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1,500 घर बनाए जाएंगे। नींव का काम शुरू होने के छह महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। आरामदायक, मज़बूत और ज्यादा मज़बूत प्री-फैब्रिकेटेड घर बनाने के लिए खास तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2019 के बाद, हमने एक नया J&K UT बनाने को बढ़ावा देने के लिए नई एनर्जी के साथ काम किया है। मज़बूत इच्छा शक्ति के साथ, हमने एक नया J&K UT बनाया है जो पुरानी संस्कृति की शान पर गर्व करता है और 21वीं सदी के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद लेता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, हमने एक ऐसा J&K बनाया है, जो गरीबों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को काफ़ी सुविधाएँ और नए मौके देता है।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले पाँच सालों में रामबन और उधमपुर के बदलाव लाने वाले और तेज़ी से हुए विकास के बारे में भी बताया, और प्रशासन के बराबर विकास के वादे को दिखाया।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामबन को 355 करोड़ रुपये और उधमपुर को 328.51 करोड़ रुपये दिए हैं। यह बड़ा हिस्सा उन ज़रूरी सड़क प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए है जो उन बस्तियों को जोड़ने के लिए हैं जो अभी तक जुड़ी नहीं हैं।

रामबन में आतंकवाद के शिकार लोगों के 13 करीबी रिश्तेदारों (NoKs) को सरकारी नौकरी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि बाकी योग्य परिवारों को जल्द ही उनकी नियुक्ति मिल जाएगी।

शीतलहर के कारण घाटी के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट

श्रीनगर, 29 नवंबर । कश्मीर घाटी में शुक्रवार रात भी ठंड जारी रही और ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान में तेज़ी से गिरावट आई। इस दौरान शीत लहर का प्रकोप भी बना रहा।

लगातार गिरावट के बाद कई इलाकों में तापमान जमावट बिंदु भी नीचे चला गया जिससे सर्दी और बढ़ने का संकेत मिलता है।डेटा के मुताबिक श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि काज़ीगुंड में तापमान शून्य से नीचे 3.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पहलगाम शून्य से नीचे 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, उसके ठीक बाद कुपवाड़ा शून्य से नीचे 4.9 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पंपोर में बर्फीला शून्य से नीचे 6.0 डिग्री सेल्सियस और अवंतीपोरा में शून्य से नीचे 5.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जिससे दोनों जगहें पिछले दिन की तुलना में काफी ठंडी हो गईं।

इसी बीच कोकरनाग में शून्य से नीचे 1.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में शून्य से नीचे 1.3 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर एयरपोर्ट पर शून्य से नीचे 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तरी कश्मीर में ज़ेथन राफ़ियाबाद में शून्य से नीचे 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जबकि ज़ोजिला दर्रा सबसे ठंडा रहा जहाँ तापमान शून्य से नीचे 16.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

जम्मू संभाग में ज्यादातर इलाके जमावट बिंदू से ऊपर रहे जिससे कश्मीर के मुकाबले कुछ राहत मिली। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 8.6 डिग्री सेल्सियस और कठुआ में 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हालांकि, बनिहाल शून्य से नीचे 0.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, इसके बाद भद्रवाह 0.4 डिग्री सेल्सियस, उधमपुर 4.0 डिग्री सेल्सियस, राजौरी 1.2 डिग्री सेल्सियस और बटोत 4.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा।

लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी रही क्योंकि यहां तापमान और गिर गया। लेह में शून्य से नीचे 9.0 डिग्री सेल्सियस, कारगिल गिरकर शून्य से नीचे 10.2 डिग्री सेल्सियस हो गया और नुब्रा घाटी शून्य से नीचे 8.5 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ठंडी रही जो अब तक के मौसम की सबसे कठोर रातों में से एक थी।

370 हटाना भारत के एकीकरण परियोजना का पूर्ण होना: नड्डा

श्रीनगर, 29 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले ने वल्लभभाई पटेल के पूर्ण रूप से एकीकृत भारत के सपने को साकार किया, यह दावा करते हुए कि यह संवैधानिक प्रावधान लंबे समय तक राष्ट्रीय एकता, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बाधा बना हुआ था।

समाचार एजेंसी के अनुसार, वडोदरा में आयोजित Sardar@150 यूनिटी मार्च' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर देश के बाकी हिस्सों के समान संवैधानिक ढांचे पर आ गया।

नड्डा ने कहा कि पटेल ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को तो सुनिश्चित कर दिया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के नेतृत्व द्वारा लिए गए बाद के राजनीतिक निर्णयों ने राज्य को देश के अन्य हिस्सों की तरह समेकित होने से रोक दिया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद छह दर्जन से ज्यादा आतंकी लॉन्चपैड पाकिस्तान के डेथ एरिया में शिफ्ट कर दिए गए हैं : बीएसएफ डीआईजी

जम्मू, 29 नवंबर । ऑपरेशन सिंदूर के बाद छह दर्जन से ज्यादा आतंकी लॉन्चपैड पाकिस्तान के डेथ एरिया में शिफ्ट कर दिए गए हैं और अगर सरकार सीमा पार अभियान फिर से शुरू करने का फैसला करती है तो फोर्स दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों ने शनिवार को यह बात कही।

बीएसएफ डीआईजी विक्रम कुंवर ने जम्मू में मिडिया को बताया कि बीएसएफ 7-10 मई तक चार दिनों की झड़पों के बाद मिलिट्री एक्शन में रोक का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ द्वारा सीमा पर कई आतंकी लॉन्चपैड तबाह करने के बाद, पाकिस्तान सरकार ने ऐसी सभी सुविधाओं को डेथ एरिया में शिफ्ट कर दिया। लगभग 12 लॉन्चपैड

सियालकोट और ज़फ़रवाल के डेथ एरिया से काम कर रहे हैं जो असल में सीमा पर नहीं हैं। इसी तरह सीमा से दूर दूसरे डेथ एरिया में 60 लॉन्चपैड काम कर रहे हैं।

कुंवर ने बीएसएफ आईजी जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद और डीआईजी कुलवंत राय शर्मा के साथ मिलकर 2025 में फोर्स की उपलब्धियों को बताने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में इसकी भूमिका भी शामिल है, जो अप्रैल में भारत का मिलिट्री रिस्पॉन्स था। पहलगाम हत्याकांड, जिसके तार बॉर्डर पार से जुड़े थे और जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।

अधिकारी ने कहा कि इन लॉन्चपैड्स और उनमें मौजूद आतंकवादियों के आंकड़े बदलते रहते हैं। डीआईजी विक्रम कुंवर ने बताया कि वे वहां हमेशा नहीं रहते। ये लॉन्चपैड्स आम तौर पर तब सक्रिय होते हैं जब आतंकवादियों को (भारत में) भेजना होता है... उन्हें दो या तीन से ज्यादा ग्रुप में नहीं रखा जाता। उन्होंने बताया कि अभी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाकों में कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं हैं। रिपोर्ट्स में आम तौर पर कहा जाता है कि लॉन्चपैड्स में तैनाती होती है जो आतंकवादियों को दूसरे इलाकों में ले जाने से पहले ट्रेनिंग का इशारा है। पहले उनके पास ऐसे इलाके मार्क होते थे जहां जैश-ए-मोहम्मद के लोग नीचे की तरफ सक्रिय होते थे, और लश्कर-ए-तैयबा के लोग ऊपर की तरफ सक्रिय होते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने एक मिला-जुला ग्रुप बना लिया है और जो लोग चाहें वे मिक्स्ड ग्रुप में ट्रेनिंग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू करने का फैसला करती है, तो बीएसएफ उसके ऑर्डर मानने के लिए तैयार है। अगर हम 1965, 1971, 1999 के कारगिल युद्ध, या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो बीएसएफ को सभी तरह के युद्धों का अच्छा अनुभव है, चाहे वह कन्वेंशनल हो या हाइब्रिड वॉरफेयर। हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम मई में किए गए नुकसान से ज्यादा नुकसान पहुँचाने में सक्षम हैं। सरकार जो भी पॉलिसी तय करेगी बीएसएफ उसमें अपनी भूमिका निभाएगी।

सरकार 9 नए सतत पर्यटन स्थलों का करेगी विकासः मुख्यमंत्री

श्रीनगर, 29 नवम्बर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार एक बड़े सतत पर्यटन परियोजना के तहत नौ नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह नई पर्यटन पहल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास और स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर आधारित होगी। कश्मीर चैप्टर ऑफ़ SKAL International—एक वैश्विक ट्रैवल और टूरिज़्म नेटवर्क—का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन या कोई भी उद्योग जो स्थानीय लोगों को लाभ नहीं पहुंचाता, वह उद्योग ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। समारोह को संबोधित करते हुए, जैसा कि समाचार एजेंसी ने बताया, मुख्यमंत्री ने SKAL International की विचारधारा को कश्मीर की पर्यटन

भावना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ बताया।

उन्होंने कहा, यदि आप स्वरुको देखें और कश्मीर के पर्यटन को देखें, तो दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से तालमेल दिखाई देता है। SKAL एक नॉर्डिक शब्द है, और इसके चार शब्दों का अर्थ है—अच्छा स्वास्थ्य, मित्रता, लंबी उम्र और खुशी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संगठन के मूल सिद्धांत मानव जीवन की बुनियादी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, जो आर्थिक सफलता से परे हैं।

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश को लेकर जम्मू में विरोध तेज

जम्मू, 29 नवंबर । श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस प्रवेश को लेकर जारी विवाद शनिवार को और तेज हो गया जब जम्मू के कई सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों ने मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देने के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में करीब 60 संगठन शामिल हुए जिन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुस्लिम छात्रों को दिए गए प्रवेश रद्द नहीं किए गए तो जम्मू बंद सहित बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघर्ष समिति के सदस्य रघुनाथ मंदिर चौक में एकत्र हुए और शहर में रैली निकालते हुए इंदिरा चौक तक पहुंचे जिसके बाद डिवीजनल कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति मेडिकल कॉलेज के पहले सत्र में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय के छात्रों को आवंटित किए जाने का विरोध कर रही है।

श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में एडमिशन विवाद गरमाया, संघर्ष समिति ने किया रोष प्रदर्शन

कठुआ, 29 नवंबर । श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में छात्रों के एडमिशन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कठुआ में नई समिति श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जिला कठुआ का गठन किया गया है। गठन के तुरंत बाद समिति ने जोरदार रोष प्रदर्शन किया और इसके बाद जिला उपायुक्त राजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के सदस्यों ने सीधे तौर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन को चेतावनी दी है। समिति ने कहा कि अगर एडमिशन नीति पर लिया गया फैसला वापस नहीं लिया गया तो वही संघर्ष फिर शुरू होगा, जैसा बम-बम बोले आंदोलन के दौरान हुआ था।

जेके सरकार ने अवैध खनन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 20 विशेष अदालतें अधिसूचित कीं

श्रीनगर, 29 नवम्बर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अपराधों की तेज़ सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश में 20 विशेष अदालतें अधिसूचित की हैं। कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति के साथ जारी की गई है। इन अदालतों को अधिनियम की धारा 30-बी के तहत नामित किया गया है, जिससे वे धारा 4(1) और 4(1) के उल्लंघनों—यानी अवैध खनन और उससे संबंधित अपराधों—की सुनवाई विशेष रूप से कर सकें। प्रत्येक विशेष अदालत अपने संबंधित जिले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगी। निम्नलिखित अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में अधिसूचित किया गया है- * अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सांबा - जिला सांबा

* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गंदेरबल - जिला गंदेरबल
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुंछ - जिला पुंछ
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांदीपोरा - जिला बांदीपोरा
* प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रियासी - जिला रियासी
* प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामबन - जिला रामबन
* प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शोपियां - जिला शोपियां
* प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किश्तवाड़ - जिला किश्तवाड़
* प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुलगाम - जिला कुलगाम
* प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडगाम - जिला बडगाम
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू - जिला जम्मू
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर - जिला श्रीनगर
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डोडा - जिला डोडा
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कठुआ - जिला कठुआ
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारामूला - जिला बारामूला
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनंतनाग - जिला अनंतनाग
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलवामा - जिला पुलवामा
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजौरी - जिला राजौरी
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उधमपुर - जिला उधमपुर
* अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हंदवाड़ा - जिला कपवाड़ा

सरकार का कहना है कि इन विशेष अदालतों की स्थापना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाना और संबंधित मामलों के तेज़ निपटारे को सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों की क्रेडिट लिंकेज को गति देने पर दिया जोर

जम्मू, 29 नवंबर । प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने संबंधित विभागों और बैंकिंग संस्थानों को निर्देश दिया कि इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट अपटेक को बढ़ाने के लिए एक बड़े रणनीतिक अभियान की शुरुआत की जाए।

उन्होंने कहा कि क्रेडिट लिंकेज इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसका प्रशिक्षण, टूलकिट वितरण एवं क्षमता निर्माण घटकों के साथ समान गति से आगे बढ़ना आवश्यक है।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह, श्रम एवं रोजगार सचिव कुमार राजीव रंजन, एमडी जे&के बैंक, निदेशक L&E, निदेशक I&C जम्मू/कश्मीर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने स्वीकृत ऋण और वास्तविक वितरण के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए *फोकस्ड हस्तक्षेप* की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों को प्रक्रियाएं सरल बनाने, विलंब कम करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि स्वीकृत लाभार्थियों को समय पर धनराशि प्राप्त हो, ताकि योजना के लाभ जमीनी स्तर तक पहुँच सकें। उन्होंने लक्ष्य रखा कि जम्मू-कश्मीर की ऋण वितरण दर को कम से कम राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत तक पहुँचाया जाए।

पुतिन की यात्रा से पहले रूसी संसद द्वारा भारत के साथ सैन्य समझौते को मंजूरी दिये जाने की संभावना

नयी दिल्ली 29 नवम्बर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने होने वाली बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा से पहले रूसी संसद के निचले सदन स्टेट डूमा में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दिए जाने की पूरी संभावना है। श्री पुतिन 23 वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए चार से पांच दिसम्बर तक भारत की दो दिन की यात्रा पर आ रहे हैं।दोनों देशों के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समर्थन समझौते (आरईएलओएस) को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। इसका उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक सैन्य सहयोग को और सुदृढ़ करना है। इस समझौते पर गत 18 फरवरी को मास्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन रक्षा उप मंत्री अलेक्ज़ेंडर फोमिन ने हस्ताक्षर किये थे। रूस की आधिकारिक समाचार एजेंसी इतर तास के अनुसार रूसी सरकार ने स्टेट डूमा में इस समझौते के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस समझौते में दोनों देश एक-दूसरे की भूमि पर सैन्य कर्मियों, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की पारस्परिक तैनाती की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। समाचार एजेन्सी के अनुसार इस प्रस्ताव में रूस और भारत के बीच उस समझौते को मंजूरी देने की बात कही गयी है जिसके तहत रूसी सैन्य इकाइयों, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती भारतीय ठिकानों पर और भारत की सैन्य इकाइयों, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती रूसी ठिकानों पर की जा सकती है

जेडीए को यह बताना होगा कि जर्नलिस्ट अरफाज डिंग के घर को गिराने का आदेश किसने दिया: उपमुख्यमंत्री

श्रीनगर 29 नवंबर । उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को कहा कि जम्मू विकास प्राधिकरण को यह बताना होगा कि जर्नलिस्ट अरफाज डिंग के घर को गिराने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल किसी भी अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कभी भी बदले की भावना से किए गए कामों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भारत के संविधान को मानता है और जर्नलिस्ट के काम की इज्ज़त करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि सरकार ने इस कदम को मंजूरी नहीं दी है इसलिए जेडीए को यह साफ करना चाहिए कि उन्होंने किसके आदेश पर यह कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अरफाज डिंग को बोलने और अपने विचार पब्लिश करने का हक है। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट को चुप कराने की कोई भी कोशिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन

को कमजोर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोगों को ज़बरदस्ती दबाना बिना नतीजों के जारी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ से इसमें शामिल परिवार को बहुत मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदार लोग अक्सर ऐसे कामों के असर को समझ नहीं पाते। उन्होंने आगे कहा कि सरकार गैर-कानूनी ऑर्डर के लिए ज़िम्मेदार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उन्होंने पूरी जांच का वादा किया।

देश-विदेश की यात्राएं करना आज के दौर में मुश्किल भरा काम नहीं है। चाहे बिजनेस के लिए यात्राएं करनी हों या एडवेंचर के लिए या फिर छुट्टियां बिताने के लिए। उन्नात ट्रांसपोर्ट और संचार साधनों से सब कुछ आसान हो गया है। टूरिज्म सेक्टर देश की जीडीपी में भी बड़ा योगदान दे रहा है क्योंकि पर्यटकों के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह बड़ा स्रोत है। इतना ही नहीं, लाखों लोगों को टूरिज्म विभाग, ट्रैवल एजेंसी, होटल, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी या फिर कार्गो कंपनियों में रोजगार भी मिला हुआ है।

टूरिज्म में इन 8 क्षेत्रों में मिलेंगे बेहतरीन मौके

वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, नए वीसा सुधार, अतुल्य भारत अभियान और सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिए जाने से भारतीय ट्रैवल एंड टूरिज्म उद्योग में आने वाले वर्षों में और तेजी आने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक, बीते कुछ वर्षों में करीब 9 प्रतिशत (3.74 करोड़) लोगों को टूरिज्म सेक्टर में रोजगार मिला। देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत ऐसी है कि दक्षिण एशिया घूमने आने वाले करीब 50 प्रतिशत पर्यटक हर साल भारत आना पसंद करते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

करियर के अवसर

चूंकि टूरिज्म उद्योग में कार्य का दायरा काफी विस्तृत है, इसलिए यहां युवाओं के लिए सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में अनेक प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं। टूरिज्म से संबंधित कोर्स करने के बाद आप विभिन्न विमानन कंपनियों, होटल आदि में मैनेजर, टूर मैनेजर, कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ट्रैवल प्रोडक्ट डिजाइनर, सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ, ट्रैवल एजुकेटर, गाइड, दुभाषिया आदि के तौर पर जॉब पा सकते हैं। इसी तरह ट्रैवल एजेंसीज में भी ढेर सारे अवसर हैं, जहां आप मैनेजर, रिजर्वेशन एंड काउंटर स्टाफ, सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ, टूर एस्कॉर्ट, टूर ऑपरेटर आदि के रूप में सेवा दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि टूरिज्म सेक्टर में आपके लिए करियर ग्रोथ और पैसा दोनों हैं। अगर चाहें, तो कुछ वर्षों के अनुभव के बाद खुद का ट्रैवल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे पासपोर्ट एंड वीसा हैंडलिंग, डेस्टिनेशन मैनेजर, ट्रैवल कंसल्टेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, एचआर, बिजनेस डेवलपमेंट, पीआर, इवेंट मैनेजमेंट जैसे दूसरे गैर-परंपरागत क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए जॉब की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मेडिकल टूरिज्म भी ऐसा ही एक उभरता हुआ नया क्षेत्र है, जहां हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए काफी स्कोप है।

कहां हैं मौके?

पर्यटन विभाग - इससे संबंधित कोर्स करने के बाद आप पर्यटन विभाग में रिजर्वेशन एंड काउंटर स्टाफ, सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ, टूर प्लानर्स, टूर गाइड जैसे पदों पर सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। यूपीएससी या पीएससी परीक्षा पास कर केंद्र व राज्यों के पर्यटन विभागों में अफसर भी बना जा सकता है।

एयरलाइंस - पर्यटन उद्योग का यह सबसे आकर्षक क्षेत्र माना जाता है। आप एयर होस्टेस, ग्राउंड सपोर्ट एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरलाइन ग्राउंड ऑपरेशन, एयरलाइन टिकिटिंग, होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म जैसे कोर्स करके यहां ग्राउंड स्टाफ या इन-फ्लाइट एसोसिएट, ट्रैफिक असिस्टेंट, रिजर्वेशन एंड काउंटर स्टाफ, क्लाइंट सर्विसिंग स्टाफ के रूप में करियर बना सकते हैं।

होटल - किसी भी देश की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा हैं होटल्स। यही कारण है कि यह क्षेत्र देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम तरह के जॉब के अवसर भी लोगों को विभिन्ना स्तरों के होटलों में मिल रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट - हवाई, सड़क, रेल और समुद्री मार्गों से परिवहन के क्षेत्र में को-ऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, ड्राइवर आदि के रूप में बड़ी संख्या में जॉब के अवसर हैं।

टूर ऑपरेटर्स - ऐसे प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट के लिए टूर की व्यवस्था करते हैं, उन्हें विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घुमाने के लिए ले जाते हैं, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि जैसे साहसिक खेलों में टूरिस्ट की मदद करते हैं। क्लाइंट की यात्रा और ठहरने का प्रबंध भी यही प्रोफेशनल्स करते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप पर्यटन स्थलों की अच्छी जानकारी रखते हैं और आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है, तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं।

टाइम शेयर कंपनीज - ऐसी कंपनियां हॉलीडे रिसॉर्ट को मैनेज करने का काम करती हैं। विदेशी कंपनियों के रिसॉर्ट के साथ भी इनका बिजनेस टाई-अप होता है। आप ऐसी कंपनियों में काम करने का मौका पा सकते हैं।

हॉलीडे कंसल्टेंसी - ट्रैवल एंड टूरिज्म उद्योग में अभी यह नया क्षेत्र है। हॉलीडे कंसल्टेंट टूर से जुड़ी हर तरह की जानकारी अपने क्लाइंट को उपलब्ध कराते हैं, जैसे क्लाइंट के लिए ट्रैवल प्लान करना, टिकट बुकिंग करना आदि।

बैंक - बैंकों में भी विदेशी मुद्रा के लिए आने वाले टूरिस्ट की मदद हेतु प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाती हैं। तमाम बैंक आजकल पर्यटकों के लिए होटल और टिकट बुकिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। बैंकों में ऐसे जॉब के लिए आम तौर पर एमबीए स्टूडेंट्स को हायरिंग में खास तवज्जो दी जाती है।

पर्सनल स्किल्स

ट्रैवल एंड टूरिज्म उद्योग में कम्युनिकेशन स्किल सबसे जरूरी है क्योंकि यहां लोगों को अक्सर पर्यटकों से बातचीत करके उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना होता है। आपका व्यवहार कुशल होना भी जरूरी है। अच्छी पर्सनैलिटी से फायदा होगा। क्षेत्र विशेष की भौगोलिक जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर हैं, तो लीडरशिप क्वॉलिटी के साथ-साथ त्वरित समस्या समाधान की क्षमता और टीमवर्क की भावना भी आपमें होना जरूरी है।

कोर्स व क्वॉलिफिकेशन

टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए डिग्री, पीजी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में कई प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष होती है। इसमें किसी भी स्ट्रीम के युवा 12वीं के बाद प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो टूरिज्म में पीजी या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। कुछ संस्थान सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं, जिसे 12वीं के बाद करके आप टूर एजेंसीज या टूर प्रमोशन एंड सेल्स कंपनियों में जॉब पा सकते हैं।

सैलरी कितनी?

टूरिज्म उद्योग में सैलरी काफी आकर्षक है। एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसीज आदि में ऐसे प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को कई मुफ्त सुविधाएं भी मिलती हैं। प्रोफेशनल्स को शुरूआत में 15 से 20 हजार रुपए प्रति माह की सैलरी आसानी से मिल जाती है। अनुभव बढ़ने पर ऐसे प्रोफेशनल्स 40 हजार से लेकर 1 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, नई दिल्ली
- दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
- कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा
- डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कौन-से कोर्स?

- बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन
- बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज
- मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट
- फाउंडेशन कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म
- ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स
- इंटीग्रेटेड डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट।

ग्रुप डिस्कशन में पीछे न रह जाएं, अपनाएं ये टिप्स

कुछ एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार आप लिखित परीक्षा में तो अच्छे अंक से पास हो जाते हैं लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन का समय आता है तो वहां विफल हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन-कौन सी बातें है जिनका ध्यान रखा जाए तो आप ग्रुप डिस्कशन में भी बाजी मार सकते हैं। सबसे पहली बात इसके लिए आपको अपडेट होने के साथ-साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए।

- जीडी के दौरान किसी एक मेंबर की और फोकस न करें। सभी पर नजर आई-कॉन्टेक्ट बनाए रखें।
- जीडी में आप अपनी बात तभी रख पाएंगे जब आपको जीडी वाले टॉपिक का नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे।
- इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब दूसरा बोल रहा हो तो उसे बीच में टोके नहीं, चाहे आप उसकी बात से सहमत न भी हों। जब आपको मौका मिले तो अपनी बात को विनम्रता के साथ कहें।
- जो भी बोलें बिलकुल साफ बोलें, वरना सामने बाकी लोगों को या तो समझ नहीं आएगा या वो आपकी बात का कोई और मतलब निकाल सकते हैं।
- ध्यान रखें कि जिस टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, उससे भटके नहीं। टॉपिक की थीम को ध्यान में रखकर उसी पर अपना व्यूज रखें।
- पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। लेकिन ध्यान रखें कि न तो किसी को नीचा दिखाना है और ही खुद को बहुत नॉलेजेबल शो करना है।
- आपको बस अपनी बात शेयर करनी है न कि किसी को मानने के लिए फोर्स करना है।
- जो भी बोलें उसमें दम होना चाहिए। आपकी बात में अगर प्वॉइंट नहीं होगा तो आप इंम्पैक्ट डालने से चूक जाएंगे।
- दूसरे जो बोल रहे हैं, उसे ध्यान से सुनें। सिर्फ खुद ही न बोलते चले जाएं। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप एक अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे।

इन 5 तरीकों से एल्यूमिनी नेटवर्किंग के जरिए ढूंढे जॉब

जॉब सर्च में एल्यूमिनी सबसे मूल्यवान नेटवर्किंग कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका प्रभावी तरीके से उपयोग करें। आज के समय में प्रभावकारी एल्यूमिनी नेटवर्किंग टेक्निक्स ज्यादा फोकस्ड होती है जिसके विशेष टारगेट, गोल और एक्शंस होते हैं। अगर आप यह सीख लें कि इनका सही तरीके से फायदा किस तरह उठा सकते हैं तो एल्यूमिनी नेटवर्किंग कॉन्टेक्ट्स बेहतरी नौकरी दिलवाने में मददगार साबित हो सकता है। आप एल्यूमिनी की नेटवर्किंग का उपयोग कर इन तरीकों से जॉब सर्च कर सकते हैं -

- एल्यूमिनी नेटवर्क का जानकारी लेने में आप अच्छा यूज कर सकते हैं। आपको टारगेट कंपनियों के एचआर मैनेजर्स को लेकर जानकारी मिलेगी और आपकी पहुंच भी बनेगी। हो सकता है कि नेटवर्किंग के जरिए आप आपने टारगेट तक पहुंच जाए। इसके लिए आपको सही एल्यूमिनी के पहचाने की जरूरत है।
- आप उस एल्यूमिनी से संपर्क कर सकते हैं जो कि कंपनी, उसके डिपार्टमेंट या मैनेजर की जानकारी दे। आप यह पता कर सकते हैं वाकई कंपनी में वैकेंसी है या नहीं। कई बार कंपनी अपनी वेबसाइट पर करंट ओपनिंग में वैकेंसी मेंशन नहीं करती लेकिन उन्हें हायरिंग की जरूरत होती है। आप बेहतर तरीके से एल्यूमिनी से यह पूछ सकते हैं।
- सही बात तो यह है कि सही एल्यूमिनी से आप आसानी से संपर्क नहीं साध सकते क्योंकि वे व्यस्त इंसान होते हैं। हालांकि अगर आपका वह साथ दें तो वे कंपनी और आपके बीच में ब्रिज का काम करेगा।
- कई बार हायरिंग मैनेजर अपने स्टाफ से किसी पोस्ट के लिए कैंडीडेट की सिफारिश चाहता है। ऐसे में यह आपके लिए अच्छी बात होती है। अगर आप एल्यूमिनी से टच में रहेंगे तो ऐसे मौके पर सबसे पहले आपका नाम ही उसके दिमाग में आएगा। साथ ही आपको यह अपना इरादा उसे बताकर रखना होगा कि अगर उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी निकलेगी तो आप इच्छुक होंगे।
- इसके अलावा एल्यूमिनी से टच में रहने पर उसे संपर्क सूत्रों के हवाले से भी आपको जॉब सर्च में आसानी होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि उसके कॉन्टेक्ट्स भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आपसे जुड़े होंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

श्रीनगर में एसकेएएल इंटरनेशनल क्लब कश्मीर चैप्टर के लॉन्च में मुख्यमंत्री उमर हुए शामिल

श्रीनगर, 29 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में एसकेएएल इंटरनेशनल क्लब, कश्मीर चैप्टर के लॉन्च में शामिल हुए जो वैश्विक पर्यटन संबंधों को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर के पर्यटन सेक्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह पहल टिकाऊ पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालिक विकास के लिए नए रास्ते खोलने के लिए तैयार है, साथ ही जम्मू-कश्मीर को ग्लोबल टूरिज्म नेटवर्क के साथ और जोड़ेगी।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसकेएएल के मुख्य मूल्य जम्मू और कश्मीर के लोकाचार से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीर में पर्यटन को देखें तो आपको एहसास होगा कि कुछ सिनर्जी हैं जो अपने आप साफ हो जाती हैं। एसकेएएल शब्द नॉर्डिक है और इन चार शब्दों का मतलब है अच्छी सेहत, दोस्ती, लंबी उम्र और खुशी।

उन्होंने कहा कि संस्था के शुरुआती सिद्धांत इंसानी जीवन की सबसे बुनियादी उम्मीदों को दिखाते हैं जो पैसे की सफलता से कहीं आगे हैं। उन्होंने कहा कि एक संस्था जिसका नाम इन चार ज़रूरी चीज़ों की निशानी है, वह प्रॉफ़िट या रोज़मर्रा की दूसरी चिंताओं के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो हम एक-दूसरे के लिए चाहते हैं-अच्छी सेहत, दोस्ती, लंबी ज़िंदगी और खुशी मुख्यमंत्री ने बताया कि एसकेएएल की दोस्तों के साथ बिज़नेस की सोच जम्मू-कश्मीर के टूरिज़्म ग्रुप की भावना को दिखाती है। उन्होंने कहा कि यहां, इंडस्ट्री में मेरे कई दोस्त एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन में हो सकते हैं, फिर भी वे दोस्त बने रहते हैं। वे साथ बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, एक-दूसरे की इज्ज़त करते हैं और एसकेएएल ठीक यही बात करता है।

डॉ प्रदीप और अन्य ने उमेश कुमार गब्बर को जम्मू दक्षिण जिला निकाय में मनोनीत होने पर बधाई दी

जम्मू, 29 नवंबर (हि.स.)। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप महोत्रा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष आदर्श जठियार और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विजय आनंद गिल के साथ भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में भाजपा जम्मू दक्षिण जिला निकाय में उमेश कुमार गब्बर के मनोनयन पर बधाई दी। डॉ. प्रदीप महोत्रा ने गब्बर को बधाई देते हुए कहा कि उनका मनोनयन पार्टी की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निरंतर जन-भागीदारी को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार हमेशा जन शिकायतों के समाधान और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अथक प्रयास करने में अग्रणी रहे हैं। पूर्व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में उनके अनुभव ने पार्टी के आधार के विस्तार में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वह जिला टीम में और अधिक जीवंतता और प्रभावशीलता लाएंगे। आदर्श जठियार ने उमेश गब्बर की संगठनात्मक कुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उमेश गब्बर जमीनी स्तर से अपनी मज़बूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। जो पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जम्मू दक्षिण के संगठनात्मक ढाँचे को मज़बूत करने में उनकी सक्रिय भूमिका की आशा करते हैं।

जीएमसी जम्मू में चोपड़ा नर्सिंग होम गेट और रिंग रोड का उद्घाटन, आपातकालीन पहुंच में सुधार

जम्मू, 29 नवंबर (हि.स.)। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू में चोपड़ा नर्सिंग होम गेट और रिंग रोड का नया निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शनिवार को इसे औपचारिक रूप से उपयोग के लिए खोल दिया गया। लगभग 2.43 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह बुनियादी ढांचा परियोजना अब एंबुलेंसों के लिए समर्पित मार्ग उपलब्ध कराती है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल तक पहुंच का समय कम होने की उम्मीद है। घनी आबादी वाले बख्शी नगर क्षेत्र में अक्सर लगने वाले जाम को देखते हुए इस नए रास्ते से गंभीर मरीजों को जीएमसी की आपात सेवाओं तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही अस्पताल परिसर के आसपास यातायात दबाव में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है।उद्घाटन अवसर पर मौजूद विधायक जम्मू वेस्ट अरविंद गुप्ता ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में तेजी आएगी और अस्पताल प्रशासन व आम लोगों दोनों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के विकास कार्य जरूरत के आधार पर आगे भी जारी रहेंगे। परियोजना के उद्घाटन के दौरान जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल एवं डीन डॉ. अशुतोष गुप्ता, विभिन्न अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, विभागाध्यक्ष और फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने इस परियोजना के संस्थागत महत्व को रेखांकित किया। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा पूरा किया गया। विभाग के एक्सईएन संदीप महाजन और उनकी टीम ने समयबद्ध और गुणवत्ता के अनुरूप कार्य निष्पादन के लिए सराहना प्राप्त की। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधि और स्थानीय संगठन पदाधिकारी भी शामिल हुए। नए मार्ग के शुरू होने के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि क्षेत्र में आपातकालीन पहुंच और यातायात प्रबंधन दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।

नेकां सरकार पर बाली भगत का हमला, कहा विभागीय असंगति प्रशासनिक विफलता का संकेत

जम्मू, 29 नवंबर (हि.स.)। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व वाली उमर अब्दुल्ला सरकार पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार अपने ही विभागों पर नियंत्रण रखने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय प्रमुख बिना मंत्रियों से सलाह किए बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे गंभीर प्रशासनिक विफलता उजागर होती है। बाली भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी लगातार जिम्मेदारी को एलजी प्रशासन पर डालते हैं जबकि संबंधित विभाग सीधे तौर पर उनके मंत्रियों के अधीन हैं। हाल ही में जम्मू में एक पत्रकार के घर पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विवादों के समय खुद को जिम्मेदारी से अलग करने की कोशिश करती है।

उन्होंने कहा कि अगर मंत्रियों को अपने विभागों में हो रहे कार्यों की जानकारी नहीं है, तो यह प्रशासन के ढांचे के ढहने का संकेत है। और अगर जानकारी होने के बावजूद वे दूसरों पर दोष डालते हैं तो स्थिति और भी चिंताजनक है।

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि एनसी सरकार राज्य में अधिकार और पुनर्गठन की मांग तो करती है लेकिन बुनियादी शासन अनुशासन भी प्रदर्शित नहीं कर पा रही। उन्होंने सवाल किया कि जब मंत्रियों और विभागीय प्रमुखों के बीच समन्वय नहीं है तो यह सरकार बड़े दायित्व कैसे संभाल सकती है। भगत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग स्पष्ट, उत्तरदायी शासन की उम्मीद करते हैं, न कि बहानों और भ्रम पर आधारित राजनीति की। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी निर्णय प्रक्रिया की जवाबदेही लेनी चाहिए और हर विवाद में दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है।

'एनसी कार्य समिति की बैठक शासन की विफलता और ध्रुवीकरण के नए एजेंडे को उजागर करती है'

श्रीनगर, 29 नवंबर (हि.स.)। श्रीनगर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुप्रचारित कार्यसमिति की बैठक जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए पूरी तरह से निराशाजनक रही। नागरिकों को शासन के पूरी तरह ध्वस्त होने, अधूरे चुनावी वादों और शांति, विकास और प्रगति के लिए एक ठोस रोडमैप पर स्पष्टता की उम्मीद थी। इसके बजाय दो दिनों के विचार-विमर्श के बाद नतीजा एक और विश्वासघात है - कुछ भी ठोस नहीं, कुछ भी आश्वस्त करने वाला नहीं, कुछ भी दूरदर्शी नहीं।

यह बात भाजपा जेके-यूटी के पूर्व एमएलसी और प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने कही। तथाकथित संकल्प नये नहीं हैं। जीएल रैना ने कहा कि ये केवल पुरानी बयानबाजी की पुनरावृत्ति है जिसे जनता पहले ही खारिज कर चुकी है।

उन्होंने कहा यदि कार्य समिति की ओर से कोई स्पष्ट संदेश है तो यह केवल असहमति को शांत करने और वंशवादी पदानुक्रम के प्रति वफादारी सुनिश्चित करने का इरादा है। उन्होंने आगे कहा इसमें भी नेतृत्व कमजोर और अनिर्णायक दिखाई दिया और अपने ही भीतर तथाकथित अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई करने में असमर्थ रहा।

गौरव ने भारत की 8.2% जीडीपी वृद्धि की सराहना की

जम्मू, 29 नवंबर (हि.स.)। जुलाई-सितंबर तिमाही में अपेक्षा से कहीं अधिक 8.2% जीडीपी वृद्धि की जम्मू-कश्मीर भाजपा ने प्रशंसा की है। गौरव गुप्ता ने कहा कि ये आँकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक मजबूती की पुष्टि करते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए गुप्ता ने कहा कि मज़बूत विनिर्माण और सेवाओं में दोहरे अंकों के विस्तार से प्रेरित छह तिमाहियों की उच्च वृद्धि दर ने साबित कर दिया है कि कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। गुप्ता ने कहा, अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ़ उपायों और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल के बावजूद, भारत ने असाधारण आर्थिक मजबूती दिखाई है।

कॉन्ग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिला-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया

जम्मू,, 29 नवंबर (हि.स.)। कुलगाम में इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस ने शनिवार को संगठन सृजन अभियान के तहत जिला-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और आगामी संगठनात्मक प्रक्रियाओं से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस पर्यवेक्षक जैन रुमुल्लाह अकील ने की जिन्होंने ब्लॉक, बूथ और ज़िला स्तर के कार्यकर्ताओं से विस्तार से बातचीत की और उनकी चिंताओं, सुझावों एवं राजनीतिक गतिविधियों पर फीडबैक सुना। अकील ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी के स्पष्ट निर्देशों के तहत कॉन्ग्रेस ने देशभर में सभी जिलों में जिलाध्यक्षों के चुनाव को पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित करने के लिए अभियान शुरू किया है।

महात्मा गांधी-सच्ची देशभक्ति की आत्मा विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

कठुआ, 29 नवंबर (हि.स.)। टाइनी स्कॉलर्स स्कूल कठुआ में बड़े उत्साह के साथ एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय सच्ची देशभक्ति की आत्मा - महात्मा गांधी था।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आना जम्वाल तहसीलदार नगरी जेकेएएस और विशिष्ट अतिथि सुषमा महाजन जिला अध्यक्ष भाजपा कठुआ महिला मोर्चा उपस्थित थीं।

इस अवसर पर निदेशक मनीषा गुप्ता भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्या रीना खजूरिया के औपचारिक स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलन और विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। छात्रों ने महात्मा गांधी के मूल्यों, आदर्शों और देशभक्ति की भावना को दर्शाते हुए प्रभावशाली और भावपूर्ण भाषण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का निर्णायक मंडल पूनम नंदा

और शिखा मेहरा ने किया। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं की घोषणा की गई और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए योग्य छात्रों को ट्रॉफी प्रदान की गई। पूरे कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ समन्वयक प्रेरणा खजूरिया ने किया और संचालन आनंदिका ने किया। कनिष्ठ वर्ग में प्रथम पुरस्कार भाग्यश्री, दूसरा पुरस्कार अनाया सिंह और परिन गुप्ता, तीसरा पुरस्कार लक्ष्य हंस और आराध्या शर्मा को दिया गया। इसी प्रकार सांत्वना पुरस्कार अंशिका, रेधन्या राजपूत और डोल्से भाऊ को दिया गया।

सेना के जेसीओ की दिल का दौरा पड़ने से मौत

पुंछ, 29 नवंबर (हि.स.)। पुंछ जिले के खारी इलाके में तैनात सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर (जेसीओ) की शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि मृतक हवेली तहसील में पुलिस स्टेशन पुंछ के तहत पुलिस पोस्ट खारी में तैनात थे।

जानकारी के अनुसार उन्हें पोस्ट पर ज़ोरदार दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच शुरू की गई है।

कठुआ विधायक ने विश्वविद्यालय अन्वेषण मेला 2025 का किया उद्घाटन

कठुआ, 29 नवंबर (हि.स.)। कठुआ विधायक डॉ. भारत भूषण ने कठुआ में विश्वविद्यालय अन्वेषण मेला 2025 का उद्घाटन किया। देश के बीस से अधिक शीर्ष विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने एक दिवसीय मेले में भाग लिया। यह मेला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू प्रांत के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें कठुआ के एक दर्जन से अधिक निजी स्कूलों के साथ-साथ 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय अन्वेषण मेले का मुख्य उद्देश्य छात्रों को 12वीं के बाद उपलब्ध करियर और अध्ययन के अवसरों से अवगत कराना था। कठुआ के विधायक ने अपने संबोधन में इस अनोखे मेले के आयोजन की सराहना की, जो छात्रों को आगे की पढ़ाई के अवसरों का पता लगाने और सही करियर के अवसर चुनने के लिए ज्ञान से लैस करेगा।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू के महासचिव सत पॉल मनसोत्रा, लिटिल एंजेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की रजनी खुल्लर, नव जागृति एचएसएस के डॉ. मदन मोहन शर्मा, आरएस गोल्डन एचएसएस खरोट मोड़ के जसबीर सिंह, ऋग्वेद हाई स्कूल के प्रधानाचार्य, लर्निंग टेम्पल इंग्लिश स्कूल के नरेश कुमार, बालक एवं बालिका एचएसएस कठुआ के प्रधानाचार्यों ने अपने संस्थानों के छात्रों के साथ मेले में सक्रिय रूप से भाग लिया। मेले में भाग लेने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, जम्मू विश्वविद्यालय, टाइम्स ग्रुप बेंडिट यूनिवर्सिटी, श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सिद्धि विनायक कॉलेज ऑफ नर्सिंग शामिल थे। लिटिल एंजेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ के लॉन में आयोजित विश्वविद्यालय अन्वेषण मेले में 1000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

प्रगतिशील समाज के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका : राणा

मेंढर, 29 नवंबर (हि.स.)। जल शक्ति, वन पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं जनजातीय कार्य मंत्री जावेद अहमद राणा शनिवार को मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव लर्निंग धारणा मेंढर के वार्षिक दिवस 2025 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों द्वारा जीवंत सांस्कृतिक, शैक्षणिक और रचनात्मक प्रदर्शनियाँ प्रस्तुत की गईं।

मंत्री ने बच्चों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट प्रतिभा, अनुशासन और आत्मविश्वास की सराहना की और एक उत्साहजनक एवं समृद्ध शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने में शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में मंत्री ने एक प्रबुद्ध और प्रगतिशील समाज के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से मेंढर जैसे दूरदराज क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि की। युवाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने छात्रों से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का आग्रह किया और विभिन्न युवा-उन्मुख और शैक्षिक पहलों के माध्यम से उन्हें निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

बजट की समीक्षा बैठक में विभागों को बाधाओं को दूर करने के दिए निर्देश

कठुआ, 29 नवंबर (हि.स.)। चालू वित्त वर्ष के लिए जिला पूंजीगत व्यय बजट के अंतर्गत कार्यों की प्रगति का आकलन करने हेतु डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई, पीडीडी और पीडब्ल्यूडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए पंचायती राज संस्थान, बीडीसी, डीडीसी, एपीडीपी और एबीडीपी घटकों के अंतर्गत कार्यान्वयन की गति की क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष से आगे बढ़ाए गए कार्यों की स्थिति का भी आकलन किया और अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उपायुक्त ने क्षेत्रीय अधिकारियों को किसी भी बाधा की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से स्थलों का दौरा करने, हितधारकों के साथ समन्वय करने और जमीनी स्तर पर सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेज

उधमपुर, 29 नवंबर (हि.स.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत आज उधमपुर में एआई सीसी पर्यवेक्षक उदय भान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

इस दौरान जिला अध्यक्ष पद के इच्छुक कार्यकर्ताओं को आवेदन फॉर्म भी वितरित किए गए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय भान ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान-राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी-ने जिला अध्यक्षों के चुनाव और संगठन निर्माण को लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में अब वही कार्यकर्ता आगे लाए जाएंगे जो संगठन के प्रति निष्ठावान, सक्रिय और जनता के बीच लगातार काम कर रहे हैं।

उदय भान ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे पर निर्भर करता है। इसलिए कार्यकर्ताओं की मेहनत का सम्मान, पारदर्शिता और समर्पित नेताओं को जिम्मेदारी देना इस अभियान की मूल भावना है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अभियान कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा देगा।

जीसीडब्ल्यू परेड ग्राउंड में एआई टूल्स पर तीन दिवसीय हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का समापन

जम्मू, 29 नवंबर (हि.स.)। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमन (जीसीडब्ल्यू) परेड ग्राउंड में एआई फॉर डिजिटल रेडीनेस एंड एडवांसमेंट (एआईडीआरए) और डेटालीड्स के सहयोग से तीन दिवसीय हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप विशेष रूप से डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम की छात्राओं के लिए आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके शैक्षणिक व पेशेवर उपयोग से अवगत कराना था।

वर्कशॉप का संचालन रिसोर्स पर्सन डॉ. रविया गुप्ता ने किया जिन्होंने छात्राओं को इंटरएक्टिव एक्सरसाइज के माध्यम से विभिन्न एआई टूल्स का वास्तविक-जीवन उपयोग समझाया।

पूरे कार्यक्रम का समन्वय जीसीडब्ल्यू परेड ग्राउंड के फैकल्टी सदस्य आकाश कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने सभी सत्रों के सहज संचालन और छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की।

समापन सत्र के दौरान डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम की डीन डॉ. अल्पना वोहरा ने कहा कि यह वर्कशॉप छात्राओं के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने से छात्रों ने न केवल अपनी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया है, बल्कि तकनीक के नवाचारपूर्ण उपयोग के प्रति आत्मविश्वास भी विकसित किया है। छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ तीन दिवसीय वर्कशॉप संपन्न हुई।

इस पहल ने उच्च शिक्षा में तकनीक-आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया और एआई साक्षरता व नैतिक प्रथाओं को मजबूत करने में एआईडीआरए तथा डेटालीड्स जैसे संगठनों के सहयोग की महत्ता को उजागर किया।

हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट ने कश्मीर के जीआई क्राफ्ट्स पर शानदार टेबल बुक लॉन्च की

श्रीनगर, 29 नवंबर (हि.स.)। कश्मीर की रिच क्राफ्ट विरासत का जश्न मनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक अहम पहल के तहत डायरेक्टरेट ऑफ़ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन-रजिस्टर्ड क्राफ्ट्स और उन्हें ज़िंदा रखने वाले मास्टर कारीगरों को समर्पित एक शानदार हार्ड-कवर टेबल बुक लॉन्च की।

आज यहां जारी एक प्रेस वार्ता में विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कश्मीर के मशहूर क्राफ्ट्स की असली पहचान कल्चरल वैल्यू और इकोनॉमिक पोटेंशियल को बचाने के लिए जीआई हासिल करना बहुत ज़रूरी है।

उन्होंने कहा, क्राफ्ट टेबल बुक इन जीआई रजिस्टर्ड खजानों और उनके पीछे के उस्तादों के सुनहरे हाथों की कहानियों को खूबसूरती से एक साथ जोड़ती है जो देखने में अच्छा लगने के साथ-साथ एक भरोसेमंद रेफरेंस भी है। यह पहल यूनेस्को सिटीज़ नेटवर्क के तहत कश्मीर के फ्लैगशिप प्रोग्राम क्राफ्ट सफारी का एक अहम हिस्सा है जिसमें श्रीनगर को 2021 में

क्राफ्ट्स और लोक कला का क्रिएटिव शहर बनाया गया है और यह बड़े सोलफुल कश्मीर ब्रांड प्रमोशन कैंपेन के तहत शुरू की गई बहुत पसंद की जाने वाली 'अपने कारीगर को जानें' सीरीज़ को आगे बढ़ाता है।

कश्मीर में अभी 15 जीआई रजिस्टर्ड क्राफ्ट्स हैं जैसे हाथ से बुनी हुई कालीन, सोज़नी और कानी शॉल, पेपर माशे, अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, खतमबंद, वाग्गुव, गब्बा और नुम्दा और अभी कॉपर और सिल्वरवेयर जैसे 6 और क्राफ्ट्स के लिए डोजियर तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री में पेश किया जाएगा।

डिपार्टमेंट की रिसोर्स सेल टीम द्वारा खूबसूरती से डिज़ाइन की गई और प्रीमियम हार्ड-कवर फॉर्मेट में प्रिंट की गई, टेबल बुक एक कलेक्टर का आइटम और कश्मीर की क्राफ्ट विरासत का एंबेसडर बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, आने वाले हफ़्तों में, जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाहर सभी बड़े सरकारी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, बड़े बिज़नेस एसोसिएशन, होटल मालिकों, रेस्टोरेंट और ज़रूरी स्टेकहोल्डर्स को कॉम्प्लिमेंट्री कॉपी बांटी जाएंगी।

प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि यह पब्लिकेशन दुनिया के खास मार्केट में कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट की अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई क्षमता की गहरी समझ पैदा करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन कभी न बदलने वाली ज़िंदा परंपराओं को बचाने के लिए मिलकर किए गए वादे को मज़बूत करेगा।

संपादकीय

सिस्टम में बड़ी गलती

यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमेशा बिज़ी रहने वाले सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह में सिर्फ़ एक दिन में लगभग 40 डॉक्टर और पैरा-मेडिकल प्रोफेशनल काम से गायब हो गए, क्योंकि ये आंकड़े जम्मू-कश्मीर की बुरी कहानी बयां कर रहे हैं, जहाँ इतना बड़ा स्टाफ बिना इजाज़त के गैरहाज़िर रह सकता है, वह भी तब, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार को कानून-व्यवस्था की ताकत वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं।

खबर है कि बिश्नाह के MLA डॉ. राजीव कुमार भगत ने सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह का सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर गैरहाज़िर का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें 39 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बिना मंजूर छुट्टी या पहले से बताए ड्यूटी से गैरहाज़िर पाए गए।

यह मौजूदा सरकार के तहत किसी कर्मचारी के काम से गैरहाज़िर रहने का पहला मामला नहीं है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद जम्मू जिले के एक हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन के हालात को देखते हुए, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट की हालत का अंदाज़ा लगा सकता है, अगर उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टरशिप में UT सरकार को ये पावर वापस मिल जाती हैं।

यह सही समय है कि मौजूदा सरकार पहले अपना घर ठीक करे, फिर सिक्योरिटी मामलों और लॉ एंड ऑर्डर जैसे और पावर मांगें।

यह सच में मंजूर नहीं है कि J&K के लोगों को सरकारी कर्मचारियों के ऐसे ढीले रवैये का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो ज़रूरी हेल्थकेयर सेंटर में पोस्टेड होने के बावजूद अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी को लेकर ज़रा भी परेशान नहीं हैं।

इस तरह के गवर्नेंस को देखकर, कोई भी समझ सकता है कि केंद्र UT सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख करने के लिए पावर देने में हिचकिचाहट क्यों दिखा रहा है।

उमर सरकार के लिए यह सही समय है कि वह कमर कस ले और यह पक्का करे कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों से पूरी सख्ती से निपटा जाए, ताकि पब्लिक सुविधाओं में सीधे तौर पर लोगों की मदद करने की ज़िम्मेदारी रखने वालों में गैरहाज़िरी और दूसरी सुस्ती को रोका जा सके।

SDH बिश्नाह के मामले में, यह साफ़ हो गया है कि स्टाफ़ के अंतर और इसके लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से मॉनिटरिंग न किए जाने के कारण लोगों को मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है, इससे साफ़ पता चलता है कि सरकार को तरीका बदलने और सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है ताकि कोई भी इस हेल्थकेयर सुविधा के कर्मचारियों के मामले की तरह बेवजह मनमानी न कर सके।

यह अच्छी बात है कि संबंधित MLA ने तहसीलदार बिश्नाह से सभी 39 गैरहाज़िर कर्मचारियों की सैलरी रोकने के लिए कहा है, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, बल्कि इस समस्या को रोकने के लिए एक ऐसा तरीका बनाया जाना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न हो।

कुल मिलाकर, सरकार में बैठे लोगों को आरामदायक कमरों में बैठकर यह मानने की अपनी सोच बदलनी चाहिए कि सब ठीक है, क्योंकि इसी मामले ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया है कि सब ठीक नहीं है और लोग वैसे ही परेशान हैं जैसे दशकों पहले होते थे।

श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार- विकसित भारत की ओर महत्वपूर्ण कदम

डॉ. प्रदीप कुमार जेना

सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 21 नवंबर 2025 से चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। संसद से पारित ये सुधार अब धरातल पर लागू हो चुके हैं। इसके बाद मीडिया में इन श्रम संहिताओं के असर को लेकर तरह-तरह की राय और खबरें सामने आ रही हैं, जिन पर बहस भी हो रही है। इस लेख का मकसद उन गलतफहमियों को दूर करना है, जो इन नई संहिताओं के असर को लेकर पैदा हो रही हैं। सरकार हमेशा से मजदूरों की गरिमा बनाए रखने के लिए मजबूत श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करती रही है। लेकिन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं होते, उन्हें अच्छे और ज्यादा रोजगार के अवसर मिलना भी ज़रूरी है। भारत जैसे श्रम-प्रधान देश में यह संभव नहीं कि सरकार सभी के लिए नौकरी पैदा करे। ऐसे में निजी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बशर्ते कि देश में ऐसा सामाजिक और कानूनी ढांचा हो जो आधुनिक, प्रगतिशील और 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप हो। नए लेबर कोड इ सी सोच को आगे बढ़ाते हैं।

कई दशकों तक भारत का श्रम तंत्र 29 केंद्रीय कानूनों के आधार पर चलता रहा, जिनमें से कई कानून आज़ादी से पहले के समय के थे। कानूनों की अधिक संख्या, उनकी जटिलता और पुराने प्रावधानों से पैदा होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, और वर्ष 2002 की दूसरी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, भारत सरकार ने देश के श्रम इतिहास में सबसे बड़े सुधारों में से एक की शुरुआत की। सरकार ने चार व्यापक श्रम कोड बनाए- वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 202

और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य परिस्थितियां संहिता 2020। ये सुधार 1991 के उदारीकरण और संरचनात्मक सुधारों के बाद सही क्रम में उठाया गया एक बड़ा कदम हैं। इनके माध्यम से भारत को एक आधुनिक, नवाचार-आधारित और प्रगतिशील श्रम व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास का मजबूत ढांचा मिलता है। श्रम सुधार- पुराने श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाकर, चार नए श्रम कोड ने पूरे नियमों की व्यवस्था को काफी सुगम कर दिया है। पहले 29 कानूनों में कुल 1,228 धाराएं थीं, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ 480 कर दिया गया है। इसी तरह, नियम 1,436 से घटकर 351 हो गए हैं, फॉर्म 181 से 73 हो गए और रजिस्टर 84 से घटकर सिर्फ 8 रह गए हैं। यह बड़ा बदलाव और एकरूपता मजदूरों के लिए जीवन को आसान बनाएगी और नियोक्ताओं के लिए काम-काज और व्यवसाय करना सरल बना देगी।

वेज कोड का एक बड़ा सुधार यह है कि अब न्यूनतम मज़दूरी सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, चाहे वे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में। पहले यह केवल कुछ तय किए गए xquot;निर्धारित रोजगारोंxquot; तक सीमित था। केंद्र सरकार के स्तर से निर्धारित की जाने वाली 'फ्लोर वेज' से क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित सीमा से कम न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर सकते।

एक सहयोगी व्यवस्था की ओर कदम है। इसके अलावा, सभी चार संहिताओं ने छोटे-छोटे उल्लंघनों को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है और पहली बार गलती के लिए समझौता प्रावधानों को शामिल किया है, जो दंडात्मक से सुधारात्मक और विश्वास-आधारित प्रणाली की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान लाया गया है। इसका मतलब है कि तय अवधि के लिए काम करने वाले कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं पाएंगे, जैसे एक साल पूरा होने पर ग्रेच्युटी का अधिकार। इससे उद्योगों को अपनी ज़रूरत के अनुसार नियुक्ति करने में लचीलापन मिलेगा, और साथ ही कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। इससे ठेके पर काम कराने की प्रथा कम होगी। अब हड़ताल या तालाबंदी से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहले सिर्फ सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर लागू था, लेकिन अब सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। इससे बातचीत और समझौते के ज़रिए विवाद सुलझाने का रास्ता मजबूत होगा और उद्योगों में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा। साथ ही, फैक्टरी, खदान और बागानों में छंटनी, ले-ऑफ और परिचालन बंद करने के मामलों में पहले सरकार से अनुमति लेने की जो सीमा 100 कर्मचारियों की थी, उसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। इससे उद्योगों को कुछ और लचीलापन मिलेगा, जबकि श्रमिकों के हितों को भी संतुलित रूप से ध्यान में रखा गया है। इस पूरे सुधार प्रक्रिया का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम सोशल सिक्योरिटी कोड है, जिसमें पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले मजदूरों को औपचारिक रूप से पहचान दी गई है। इसके साथ ही भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस नई तरह की कार्यशक्ति को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। कोड में एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का प्रावधान भी है, जिसे कई स्रोतों से वित्तीय समर्थन मिलेगा। इसका इस्तेमाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, गिग व प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा। यह कदम श्रमिक कल्याण को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक प्रयास है। इसी तरह ओएसएच कोड, जो मजदूरों की सुरक्षा, कल्याण और काम की शर्तों से जुड़ा है, कई बड़े सुधार लाता है। इसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न की सुविधा दी गई है, जिससे कारोबार करना आसान होगा। लाइसेंस अब पांच साल तक मान्य रहेगा, जो उद्योगों के लिए एक बड़ा लाभ है। यह कोड लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है। अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में और रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी सहमति और उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ। यह महिलाओं के लिए अधिक अवसरों का रास्ता खोलता है। कोड में सभी कर्मचारियों को नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच और नियुक्ति पत्र देने को अनिवार्य किया गया है, जिससे रोजगार व्यवस्था अधिक औपचारिक और पारदर्शी होगी। इसके अलावा, छोटे प्रतिष्ठानों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए कई मानकों की सीमा बढ़ाई गई है। जैसे- कॉन्ट्रैक्ट लेबर कानून लागू होने की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, फैक्टरी कानून लागू होने की सीमा बिजली के साथ 10 से बढ़ाकर 20 मजदूर और बिना बिजली 20 से बढ़ाकर 40 मजदूर कर दी गई है। इन सभी

बदलावों से श्रमिकों के लिए सुरक्षित और बेहतर कार्यस्थल बनेंगे, और उद्योगों के लिए काम करना आसान होगा। यह एक अधिक सरल, श्रमिक-अनुकूल और व्यवसाय समर्थक व्यवस्था तैयार करता है।

विकसित भारत की ओर- ये चारों श्रम संहिताएं मिलकर मजदूरों के हितों और उद्योगों की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। परिभाषाओं को सरल करने, नियमों को डिजिटल बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ, ये कोड एक ऐसी न्यायपूर्ण श्रम व्यवस्था तैयार करने की दिशा में बने हैं, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। ये क्षेत्र श्रम, कौशल और संसाधनों पर आधारित हैं। देश 2024 के 717 अरब डॉलर के मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड को 2030 तक बढ़ाकर 1.45 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की क्षमता रखता है, जब जीडीपी 7.5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इससे करोड़ों अच्छी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। चारों श्रम कोड का लागू होना इन प्रयासों को और मजबूत करेगा। ये उद्योगों को ज़रूरी लचीलापन और आसान नियम प्रदान करते हैं, साथ ही मजदूरों के लिए सार्वभौमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं।

(लेखक, आईडीएएस के अधिकारी और वर्तमान में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम सुधार निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)

राज्यों के लोक सेवा आयोगों में पारदर्शिता का संकट

- डॉ सत्यवान सौरभ

राज्यों के लोक सेवा आयोगों की स्थापना संविधान ने इस उद्देश्य से की थी कि राज्य प्रशासन में प्रतिभा, ईमानदारी और योग्यता को प्राथमिकता मिले। विडंबना यह है कि जिन आयोगों पर निष्पक्षता को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी, वे स्वयं वर्षों से पारदर्शिता के संकट से जूझ रहे हैं। अनेक राज्यों में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्र त्रुटियाँ, अस्पष्ट आरक्षण गणना और परिणामों की देरी जैसी घटनाओं ने आयोगों के प्रति जनता और युवाओं दोनों का भरोसा डगमगा दिया है। संविधान ने इन संस्थाओं को स्वतंत्र दर्जा दिया, परंतु व्यवहार में राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक सीमाएँ और संस्थागत कमजोरियाँ इनके कार्यों को प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि आयोगों की प्रक्रियाओं और संरचनाओं की गहन समीक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।

सबसे बड़ी समस्या आयोगों की नियुक्तियों से शुरू होती है। अनेक राज्यों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियाँ योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता के बजाय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु, अनुभव या पेशेवर पृष्ठभूमि को लेकर कोई स्पष्ट संवैधानिक मानदंड नहीं है। इसके कारण आयोगों पर पक्षपात व राजनीतिक पक्षधरता के आरोप लगते हैं। इसके विपरीत यूपीएससी नियुक्तियाँ पेशेवर, अनुभवी और विविध पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ अधिकारियों या शिक्षाविदों के हाथों में रहती हैं, जो उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करती हैं।

राज्यों में मानव संसाधन नियोजन भी कमजोर कड़ी है। कई बार वर्षों तक अधियाचन नहीं भेजा जाता, पद रिक्त पड़े रहते हैं, आर्थिक कारणों से भर्ती रोक दी जाती है या अधिसूचनाएँ अचानक जारी होकर फिर रद्द हो जाती हैं। यह अनियमितता पूरे चयन चक्र को बाधित कर देती है। इसके विपरीत केंद्र में 1985 में स्थापित कार्मिक मंत्रालय अधियाचन, सेवा शर्तें और भर्ती चक्र को व्यवस्थित रखता है। राज्यों में ऐसा कोई समर्पित ढाँचा न होने के कारण लोक सेवा आयोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

अवसंरचना की कमी भी आयोगों के लिए गंभीर समस्या है। कई राज्यों में सुरक्षित प्रश्नपत्र भंडारण केंद्र, एन्क्रिप्टेड डिजिटल सिस्टम, केंद्रीयकृत परीक्षा केंद्र, आधुनिक स्कैनिंग व्यवस्था और डेटा सुरक्षा तंत्र तक उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण पेपर लीक, ओएमआर गुम होने, मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों और तकनीकी विफलताओं जैसी घटनाएँ सामान्य बन गई हैं। उम्मीदवारों में भय व असंतोष का माहौल इसी अव्यवस्था से पैदा होता है।

प्रश्नपत्र निर्माण और अनुवाद में त्रुटियाँ व्यापक विवादों को जन्म देती हैं। राज्य आयोग अक्सर स्थानीय शिक्षाविदों के सीमित पैनल पर निर्भर रहते हैं, जिससे प्रश्नों का स्तर, विविधता और सटीकता प्रभावित होती है। कई बार अनुवाद में तथ्यात्मक त्रुटियाँ या अस्पष्टता रहती है, जिससे प्रश्नपत्र रद्द करने तक की नौबत आ जाती है। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की भागीदारी न होना आयोगों की गुणवत्ता को सीमित रखता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी आयोगों की आलोचना का कारण है। कई राज्यों में उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन नहीं होता। अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं के बीच समरूपता नहीं रहती, मॉडरेशन असमान होता है और अंकों का निर्धारण स्थिर मानकों पर आधारित नहीं होता। इसके कारण चयन सूची और कट-ऑफ बार-बार विवादों में घिर जाती है, जिससे मामले अदालत तक पहुँचते हैं और भर्ती वर्षों तक लंबित रहती है।

आरक्षण गणना की जटिलता भी बड़ी चुनौती है। राज्यों में क्षेत्रीय कोटा, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर आरक्षण, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला आरक्षण आदि कई स्तर होते हैं। मैनुअल गणना में त्रुटियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। छोटी-सी गलती भी पूरी चयन प्रक्रिया को संदिग्ध बना देती है, और कानूनी विवादों के कारण परिणाम अटक जाते हैं।

राज्यों के आयोग परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं कर पाते। कुछ राज्यों में पाँच-पाँच वर्षों तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं होती। तिथियों का बार-बार बदलना, परिणामों में अत्यधिक देरी और साक्षात्कार प्रक्रिया का अनिश्चित होना न केवल उम्मीदवारों के करियर को प्रभावित करता है, बल्कि आयु सीमा बढ़ने और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ भी पैदा करता है। इस तरह की अविश्वसनीयता आयोगों की साख पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक और दूरगामी सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति में योग्यता-आधारित मानक अनिवार्य किए जाने चाहिए। न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव और पेशेवर पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से निर्धारित हों। यह परिवर्तन संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

दूसरे, राज्यों में एक पृथक कार्मिक मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए, जो मानव संसाधन योजना, अधियाचन प्रबंधन और भर्ती कैलेंडर को नियंत्रित कर सके। इससे आयोगों को नियमित परीक्षा कार्यक्रम बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था UPSC की तरह स्थिरता और विश्वसनीयता पैदा करेगी।

तीसरे, आयोगों की परीक्षा प्रक्रिया का संपूर्ण डिजिटलीकरण आवश्यक है। प्रश्नपत्र निर्माण, भंडारण, एन्क्रिप्शन, सीलिंग, डिजिटल मूल्यांकन, ओएमआर स्कैनिंग और परिणाम निर्माण—all तकनीक द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। इससे पेपर लीक की संभावना कम होगी और मानव त्रुटियाँ भी नियंत्रित होंगी।

चौथे, पाठ्यक्रम का नियमित आधुनिकीकरण किया जाए। हर तीन वर्ष में विशेषज्ञ समिति द्वारा पाठ्यक्रम की समीक्षा अनिवार्य हो। आधुनिक प्रशासन, विज्ञान-तकनीक, समसामयिक चुनौतियाँ और नई नीतियाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनें, ताकि चयनित अधिकारी वर्तमान युग के अनुरूप दक्ष हों।

पाँचवें, प्रश्नपत्र निर्माण में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। अन्य राज्यों के विशेषज्ञ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञों की भागीदारी से प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता, संतुलन और विश्वसनीयता बढ़ेगी। अनुवाद में भी प्रमाणित विशेषज्ञों का उपयोग किया जाए ताकि त्रुटियाँ न्यूनतम हों।

छठे, मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना होगा। डिजिटल मूल्यांकन, दो-स्तरीय मॉडरेशन, यूनिफॉर्म स्कोरिंग गाइडलाइन और असंगत अंकों पर स्वत: समीक्षा जैसे उपाय निष्पक्षता को सुनिश्चित करेंगे। मूल्यांकनकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। सातवें, आरक्षण गणना के लिए स्वचालित डिजिटल सॉफ़्टवेयर बनाए जाएँ जिनमें निर्धारित एल्गोरिथ्म त्रुटिरहित गणना करें। इससे विवादों में भारी कमी आएगी। आठवें, राज्य भर में भर्ती कैलेंडर अधिनियम लागू होना चाहिए जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और परिणाम की अधिकतम समयसीमा निर्धारित हो। आयोग को वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी चाहिए ताकि जनता को जवाबदेही स्पष्ट हो।

नौवें, आयोग के सचिव का पद ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाए जिनके पास शैक्षणिक प्रशासन या परीक्षा प्रबंधन का गहन अनुभव हो। इससे परीक्षा लॉजिस्टिक्स, गोपनीयता, सुरक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था अधिक पेशेवर होगी। अंत में, उम्मीदवारों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र डिजिटल ग्रेविएंस पोर्टल बनाया जाए, जिससे उम्मीदवार पारदर्शी तरीके से अपनी समस्या दर्ज कर सकें, स्थिति देख सकें और समयसीमा में समाधान प्राप्त कर सकें। समापन में कहा जा सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोगों की मजबूती भारत की प्रशासनिक गुणवत्ता का आधार है। यदि आयोग पारदर्शी, तकनीक-समर्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और योग्यता-आधारित ढाँचे पर काम करें तो न केवल युवाओं का विश्वास लौटेगा बल्कि राज्य प्रशासन में दक्ष, ईमानदार और संवेदनशील अधिकारी भी मिलेंगे। सुधारों के बिना आयोगों की साख और देश के भविष्य दोनों पर प्रश्नचिह्न बने रहेंगे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

यूएन क्यों नहीं चाहता जम्मू-कश्मीर की बदलती तस्वीर देखना ?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

संयुक्त राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में भारत पर लगाए गए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर यूएन किस चश्मे से भारत को देखता है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ क्रूर आतंकवादी हमला, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए, किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं माना जा सकता है, यह राष्ट्रीय अस्मिता पर सीधा प्रहार था। हमले की औपचारिक निंदा करने के बाद यूएन विशेषज्ञ जिस तेजी से भारत सरकार की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करने में लगे दिखते हैं, वह आज इस तथ्य को उजागर करता है कि युनाइटेड नेशन की नजरें जमीन पर घट रही वास्तविकताओं से अधिक एक पूर्वनिश्चित नैरेटिव पर टिकी हुई हैं।

सवाल यह है कि क्या किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं? क्या कोई देश आतंकी वारदात के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठा रह सकता है? आतंकवाद कोई वैचारिक बहस का विषय नहीं है, यह एक हिंसक अपराध है, जिसका उद्देश्य समाज और शासन को अस्थिर करना होता है, इसलिए भारत द्वारा 2800 संदिग्धों को पूछताछ या कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लेना न तो असामान्य है और न ही अव्यवहारिक। पर यूएन ने इसे मनमानी गिरफ्तारी, यातना, भेदभाव और सामूहिक दंड का रूप देने में जरा भी संकोच नहीं किया है। यह वह अतिशयोक्ति है जो अक्सर राजनीतिक प्रेरणाओं से संचालित रिपोर्टों में दिखाई देती है। जबकि कश्मीर का सच इससे बिल्कुल उलट है।

कहना होगा कि 2019 के बाद घाटी जिस विकास पथ पर आगे बढ़ रही है, वह कई दशकों की ठहराव वाली नीतियों से बिल्कुल भिन्न है। पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, युवा उद्यमों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार पा रहे हैं। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन दिख रहे हैं जो कश्मीर को नई आर्थिक पहचान देते हैं। देश भर से निवेशक कश्मीर को संभावनाओं की भूमि के रूप में देखने लगे हैं। स्थानीय लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं कि उनके पास वह अपार अवसर हैं जो कभी चुनिंदा हाथों तक सीमित रहते थे। इसके बावजूद भी देखिए; यूएन की आई इस हालिया रिपोर्टों में इन सकारात्मक परिवर्तनों का कहीं उल्लेख नहीं होता, मानो जम?मू-कश?मीर राज?य में कश्मीर क्षेत्र केंद्र द्वारा दी जा रही प्रताड़ना, दमन और संघर्ष की कहानी ही हो!

यूएन विशेषज्ञों का लगाया गया ये आरोप भी समझ के परे है कि सरकार ने इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया, जबकि वास्तविकता यह है कि कश्मीर में इंटरनेट या संचार सेवाओं पर अस्थायी नियंत्रण सुरक्षा कारणों से किया जाता है, ताकि अफवाहें न फैलें, आतंकी नेटवर्क डिजिटल माध्यम से सक्रिय न हो सकें और किसी संवेदनशील परिस्थिति का दुरुपयोग न किया जा सके। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या मानवाधिकार केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित हैं और नागरिकों की जान की सुरक्षा कोई अधिकार नहीं?

इसी तरह विशेषज्ञों ने घरों के विध्वंस को सामूहिक दंड बताया। यह तथ्य छिपा लिया गया कि इनमें से अधिकांश मामले अवैध कब्जों, अवैध निर्माणों और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आने वाली कार्रवाई से संबंधित होते हैं। भारत में कोई भी राज्य बिना कानूनी आधार के किसी भवन को ध्वस्त नहीं करता। किंतु कश्मीर का मामला होने के कारण हर प्रशासनिक कार्रवाई को 'उत्पीड़न' की संज्ञा दे देना इस अंतरराष्ट्रीय संस्था को सबसे आसान नजर आता है।

आज यूएन ने जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव का मुद्दा उठाया है, वह एक और अतिशयोक्ति का उदाहरण है। कोई ये न भूले कि भारत में 20 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं और वे राजनीति, न्यायपालिका, सेना, प्रशासन, कला और शिक्षा हर क्षेत्र में समान अधिकारों के साथ अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यदि कहीं कोई स्थानीय अपराध या दंगा होता है तो उसे पूरे देश की सामुदायिक संरचना पर आरोप के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास गलत और विभाजनकारी है। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएँ किसी भी भेदभाव को सहन नहीं करतीं।

यूएन विशेषज्ञों ने कश्मीरी छात्रों की निगरानी पर भी सवाल उठाया है। यह तथ्य नजरअंदाज किया गया कि कई बार आतंकी संगठन छात्रों की पहचान का उपयोग ढाल की तरह करते हुए यहां लगातार पाए जा रहे हैं। हाल ही में दिल?ली कार बम ब?लास?ट की घटना हम सभी के सामने है ही, ऐसे में स?व?भाविक तौर पर संवेदनशील राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों का यह दायित्व होता है कि वे संभावित खतरों पर नजर रखें। इसे भेदभाव कहना भारत की सुरक्षा जरूरतों को न समझने और उन्हें हल्के में लेने जैसा है। यह भी समझने की जरूरत है कि कश्मीर पर रिपोर्ट बनाते समय यूएन अक्सर उन्हीं स्रोतों पर निर्भर रहता है जिनका उद्देश्य भारत के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव मजबूत करना होता है। यह उन देशों या लॉबी के प्रभाव का परिणाम है जो भारत को हमेशा विवादों में घिरा हुआ दिखाना चाहते हैं, जबकि ये संस्थाएँ यह नहीं समझतीं कि भारत अब एक ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा नीतियाँ स्वतंत्र रूप से तय करने के साथ ही अपने लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नागरिक अधिकारों और राष्ट्रीय हित में संतुलन भी स्थापित करता है। कहना होगा कि आज का कश्मीर तेजी से बदल रहा है, यह अब नई उम्मीदों और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रदेश बन रहा है। आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, पर्यटन चरम पर है और युवा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की कोशिशें लगातार कश्मीर को मुख्यधारा से और मजबूती से जोड़ने का प्रयास करती दिखती हैं, किंतु दुर्भाग्य यह है कि यूएन इन सकारात्मक परिवर्तनों को देखने की बजाय वही पुरानी नकारात्मक छवि को बार-बार दोहराने का काम करता दिखा है।

वस?तुत- सुरक्षा कार्रवाई को मानवाधिकार उल्लंघन बताने वाले विशेषज्ञों को यह समझना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया की साझा लड़ाई है और जो देश आतंकवाद का सामना करते हैं उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठा सकें। भारत की कार्रवाइयों को कानूनन, संविधानन और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के दायरे में रखते हुए समझना चाहिए न कि पूर्वाग्रहों की दृष्टि से इसे किसी के द्वारा लिया जाए। ऐसे में बेहतर होगा कि यूएन इस बदलती वास्तविकता को स्वीकार करे और भारत की संप्रभुता तथा उसकी सुरक्षा प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाए। ध?यान रहे, किसी भी अपराधी को दंड मिलना न्याय है और न्याय ही मानवाधिकारों की पहली शर्त भी है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: सुपर ओवर में अंशुल कम्बोज का कहर, हरियाणा ने पंजाब को रोमांचक मुकाबले में हराया

एजेंसी

हैदराबाद। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले में हरियाणा ने पंजाब को सुपर ओवर में मात दी। दोनों टीमों ने 20-20 ओवर में 207 रन बनाए, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर से हुआ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा की शुरुआत तेज रही। कप्तान अंकित कुमार ने सिर्फ 26 गेंदों में तूफानी 51 रन बनाए और टीम को तेज शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवरों में निशांत सिंधु ने नाबाद 61 रन (31 गेंद) बनाकर पारी को संभाला। अंत में सुमित कुमार ने 28 रनों की त्वरित पारी खेलकर हरियाणा का स्कोर 207/9 तक पहुंचाया। पंजाब की ओर से अश्वनी कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत डगमगाती रही। अभिषेक शर्मा 6 रन पर और प्रभसिमरन सिंह 20 रन बनाकर आउट हुए। दोनों को अंशुल कम्बोज ने पवेलियन भेजा। हालांकि, इसके बाद अनमोलप्रीत सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर 81 रन जड़कर टीम को वापसी दिलाई। अंतिम ओवरों में संवीर सिंह ने 16 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाकर मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचाया और पंजाब को 207 के स्कोर तक ले जाकर मुकाबला टाई करा दिया।

अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी शिविर : मुख्यमंत्री के सामने झांसी के खिलाड़ियों ने किया मल्लखम्ब का हैरतअंगेज प्रदर्शन

झांसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा स्काउट गाइड जंबूरी शिविर का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। इस जंबूरी शिविर में पूरे विश्व से 45 देशों के लगभग 16000 स्काउट गाइड प्रतिभाग कर रहे हैं। यह शिविर 29 नवम्बर तक चलेगा। इसी क्रम में करीब 61 साल बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के समक्ष एमेच्योर मल्लखम्ब एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने मल्लखम्ब पर द न्यू एरा पब्लिक स्कूल झांसी खेलों इंडिया सेन्टर के खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर अचम्भित कर दिया। मुख्यमंत्री ने शानदार प्रस्तुति देखकर मल्लखम्ब खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और मल्लखम्ब की सराहना करते हुए इस प्राचीन खेल को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्धता दिखाई । सिर्फ मल्लखम्ब के प्रदर्शन के लिए ही मुख्यमंत्री ने 10 मिनट का समय दिया था। जंबूरी स्काउट गाइड मल्लखम्ब की प्रस्तुति एमेच्योर मल्लखम्ब एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रवि प्रकाश परिहार के निर्देशन में मयंक रैकवार, अनुज प्रिंस, अंशुमन, सोनिया कुशवाहा, शुभांशी कुशवाहा, पूर्वी कुशवाहा, आरबी सिंह द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया।

विश्व किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोरखपुर के सनी सिंह का दमदार प्रदर्शन

गोरखपुर। गोरखपुर के गौरी मंगलपुर, खोराबार निवासी तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एम.ए समाज शास्त्र के छात्र सनी सिंह ने सीनियर वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। अबू धाबी में 21 से 30 नवम्बर तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सनी सिंह ने स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड जैसे मजबूत देशों के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए विश्व में 9वीं रैंक प्राप्त कर देश, प्रदेश तथा विश्वविद्यालय का नाम गौरव से ऊँचा किया सनी सिंह की इस उपलब्धि पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हर्ष की लहर है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बधाई देते हुए कहा, 'यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे छात्र ने विश्व स्तर पर जाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हमें विश्वास है कि इंडियन इंटरनेशनल कप 2026 और सीनियर एशियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2026 में उनका प्रदर्शन और भी बेहतर रहेगा। ' इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू डॉ. अनुभूति दूबे, प्रातिकुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी, डॉ मनीष पांडेय, प्रो. अनुराग द्विवेदी, प्रो. राजीव, डॉ दिपेन्द्र मोहन सिंह तथा प्रो. विजय चाहल समेत अनेक प्राध्यापकों ने सनी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

यूपी स्टेट बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैम्पियनशिप : अभिषेक, अजहर, यूसुफ, गौतम और दाऊद ने अगले दौर में बनाई जगह

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बिलियर्ड्स और स्नूकर एसोसिएशन (यूपीबीएसए) के तत्वावधान में आयोजित राजा राम कुमार भार्गव स्मृति राज्य स्तरीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैम्पियनशिप में प्रयागराज के अभिषेक केसरवानी, अजहर अमन, यूसुफ मतलूब और गौतम सिंह ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बना ली है। बिशप जॉर्ज स्कूल एंड कॉलेज में प्रतियोगिता के चौथे दिन का पहला मैच प्रयागराज के अभिषेक केसरवानी और कानपुर के ओवैस वारसी के बीच खेला गया। अभिषेक ने अपनी क्यूइंग स्किल्स से सबको हैरान करते हुए लगातार तीन फ्रेम में 3-0 से हराया। पहले फ्रेम से ही अभिषेक टेबल पर पूरी तरह से नियंत्रण में थे और कई खूबसूरत शॉट खेलते हुए फ्रेम 54-39 से जीत लिया। अगले फ्रेम में ओवैस ने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन एक ब्राउन शॉट चूक गए और अभिषेक को मौका मिला, जहां से उन्होंने पूरी तरह सफाया करते हुए फ्रेम 63-15 से जीत लिया। तीसरे फ्रेम तक ओवैस बहुत ज़्यादा दबाव में थे और उन्होंने रक्षात्मक खेलने की कोशिश की और 53 अंक बनाए।

टाटा विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल घोषित, 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगे मुकाबले

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टाटा विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। लीग का चौथा संस्करण 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा, जिसमें मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित किए जाएंगे। यह टूर्नामेंट एक बार फिर भारत और दुनियाभर की शीर्ष महिला क्रिकेटर्स के कौशल को प्रदर्शित करेगा।

सीजन की शुरुआत 9 जनवरी को नवी मुंबई में होने वाले धमाकेदार ओपनर से होगी, जहां मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा। नवी मुंबई में 9 से 17 जनवरी तक कुल 11 मैच खेले जाएंगे, जो टूर्नामेंट की रोमांचक शुरुआत तय करेंगे। इसके बाद

लीग का कारवां वडोदरा पहुंचेगा, जहां बाकी 11 मुकाबले सहित प्लेऑफ भी खेले जाएंगे। वडोदरा में पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और आरसीबी के बीच होगा, जिसके बाद 2025 फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और मुंबई के बीच हाई-वोल्टेज भिड़ंत देखने को मिलेगी। लीग चरण 01 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद एक दिन का ब्रेक निर्धारित है। एलिमिनेटर मुकाबला 3 फरवरी, मंगलवार को खेला जाएगा, जिसमें अंक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें आमने-सामने होंगी। इसके विजेता को फाइनल में जगह पाने का मौका मिलेगा। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे 5 फरवरी 2026 को वडोदरा में होने वाले फाइनल में पहुंचेगी, जहां नए डब्ल्यूपीएल चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में हुए मेगा ऑक्शन के बाद टीमों की संरचनाओं में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे डब्ल्यूपीएल 2026 अब तक का सबसे रोमांचक सीजन साबित होने की उम्मीद है। युवा भारतीय खिलाड़ियों और अनुभवी विदेशी सितारों के मिश्रण से यह टूर्नामेंट उच्च स्तरीय और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट का शानदार प्रदर्शन करेगा।

सुल्तान अज़लान शाह कप : भारत ने कनाडा को 14-3 से रौंदा, फाइनल में की जगह पक्की

एजेंसी

इपोह (मलेशिया)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को अपने आखिरी राउंड-रोबिन मुकाबले में कनाडा को 14-3 से करारी शिकस्त देकर सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 के फाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली। भारत के डिफेंडर जुगराज सिंह टीम के शीर्ष स्कोरर रहे, जिन्होंने कुल चार गोल दागे–तीन पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए। इसके अलावा अभिषेक, अमित रोहिदास और राजिंदर सिंह ने दो-दो गोल किए। वहीं सेल्वम कार्ती, निलकांत शर्मा, संजय और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल का योगदान दिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की कर ली है, चाहे दिन में बाद के मुकाबलों के परिणाम कुछ भी हों। क्रेग फुल्टन की कोचिंग में खेल रही भारतीय टीम का सामना फाइनल में संभवतः बेल्जियम से होगा–वही टीम जिसने राउंड-रोबिन चरण में भारत को एकमात्र हार दी थी। फिलहाल बेल्जियम 10 अंकों के साथ मजबूत स्थिति में है और शनिवार को बाद में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, जिसके सात अंक हैं। न्यूजीलैंड के पास फाइनल में पहुंचने की मामूली उम्मीद है, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम छह गोल के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी : हिम्मत सिंह ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर दिल्ली को दिलाई रोमांचक जीत

एजेंसी

अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुकाबले में हिम्मत सिंह ने अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर दिल्ली को तमिलनाडु के खिलाफ छह विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। आखिरी गेंद पर दो रन की जरूरत थी, तभी हिम्मत ने गुरजपनीत की गेंद को प्वाइंट के ऊपर से उछाल दिया, जहां शाहरुख खान कैच नहीं लपक सके और दिल्ली की जीत तय हो गई। इससे पहले अंतिम से एक गेंद पहले दिल्ली रन-आउट से भी बाल-बाल बची।199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को यश ढुल और प्रियांश आर्या ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 5.1 ओवर में 52 रन जोड़े। आर्या ने 15 गेंदों में 35 रन बनाए और सोनू यादव का शिकार बने। ढुल ने कप्तान नितीश राणा (26 गेंदों पर 34 रन) के साथ मिलकर रनगति बनाए रखी। ढुल ने चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 46 गेंदों पर 71 रन की शानदार पारी खेली।

उनके आउट होने पर दिल्ली को 28 रन चाहिए थे। अयुष बादोनी ने 23 गेंदों में 41 रन बनाकर टीम को जीत की राह पर बनाए रखा।

मैच में इससे पहले तुषार रहेजा (41 गेंदों पर 72 रन) और अमित साथविक (40 गेंदों पर 54 रन) की तेज अर्धशतकीय पारियों की बदौलत तमिलनाडु ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। हालांकि वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज़ी में महंगे साबित हुए और 47 रन देकर एक भी विकेट नहीं ले सके। तमिलनाडु को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि दिल्ली ने इस जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है।

बीसीसीआई विजय मर्चेंट ट्रॉफी : हिमाचल की अंडर-16 मेन टीम का चयन

एजेंसी

धर्मशाला। बीसीसीआई विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2025 के लिए हिमाचल की मेन टीम का चयन कर लिया गया है। हिमाचल की टीम प्रतियोगिता में अपना पहला मैच सौराष्ट्र के साथ खेलेगा। यह मैच 7 से 9 दिसम्बर तक विजयवाड़ा में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 12 से 14 दिसंबर तक हरियाणा के साथ, 18 से 20 दिसम्बर तक दिल्ली के साथ, 23 से 26 दिसम्बर तक महाराष्ट्र और 29 से 31 दिसंबर तक हैदराबाद के साथ होगा। सभी मैच विजयवाड़ा में ही खेले जाएंगे।

उधर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने इस टीम का चयन हैदराबाद और विजयवाड़ा में पुरुष अंडर-16 अभ्यास मैच और बीसीसीआई विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए एक साथ किया है। अंडर-16 पुरुष टीम की कमान कांगड़ा के आदिल राणा को सौंपी गई है। इसके अलावा अभय चंदेल बिलासपुर, अखिलेश गौतम बिलासपुर, प्रिंस सुरिंदर ठाकुर बिलासपुर, अक्षित ठाकुर चंबा, कनिष्क शर्मा हमीरपुर, साहिल कुमार वैभव शर्मा ऊना को टीम में शामिल किया गया है।

वहीं अजय मोहन शर्मा कोच, तरूण कुमार शर्मा सहायक कोच,

हमीरपुर, तनीश कुमार कांगड़ा, वेदांत शर्मा कुल्लू, आदिश मिन्हास मंडी, अथर्व आर्य शिमला, हार्दिक शर्मा सिरमौर, आर्यन मेहता सोलन, समीर सोलन, उत्तम परमार सोलन, भविष्य भारद्वाज ऊना, सुमित संधू ऊना, गुलशन चौधरी फील्डिंग कोच, अमृत शर्मा फिजियो, शुभम् कथूरिया ट्रेनर, संदीप भास्कर वीडियो विश्लेषक, रवि कांत पार्श्व भुजा तथा मुकेश शर्मा को प्रबंधक का जिम्मा सौंपा गया है।

यूईएफए महिला नेशंस लीग — फाइनल के पहले चरण में जर्मनी और स्पेन का मुकाबला ड्रॉ

एजेंसी

कैसरस्लॉटर्न। मौजूदा विश्व चैंपियन स्पेन ने गोलकीपर काता कॉल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत यूईएफए महिला नेशंस लीग फाइनल के पहले चरण में जर्मनी को गोलरहित ड्रॉ पर रोके रखा। अब खिताब का फैसला मंगलवार को मैड्रिड में होने वाले दूसरे चरण में होगा। मैच के दौरान जर्मनी ने गेंद पर नियंत्रण और आक्रामकता दोनों में बढ़त बनाए रखी, जबकि स्पेन ने गहरी रक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए मैच को ड्रॉ की दिशा में मोड़ने की कोशिश की। जर्मन खिलाड़ियों ने कई मौकों पर गोल के करीब पहुंचकर भी मौका गंवा दिया।

जर्मनी की स्टार स्ट्राइकर क्लारा ब्यूहल, जिन्हें पहले हाफ में चार साफ मौके मिले, ने ज़ेडडीएफ से कहा, 'हमने बेहद साहसी खेल दिखाया। गोल न कर पाने का मलाल है।' उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन टीम का आत्मविश्वास बढ़ाता है और अब वे मैड्रिड में होने वाले निर्णायक

मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं। जर्मन कोच क्रिश्चियन वुक ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने साबित किया कि वे स्पेन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ न सिर्फ टिक सकते हैं, बल्कि अपना खेल भी खेल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कई मौकों के बावजूद गोल न कर पाना निराशाजनक रहा। मैच से पहले जर्मनी ने स्पेन से यूरो 2025 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने की बात कही थी, लेकिन स्पेन ने उनकी हर कोशिश को नाकाम किया। हालांकि, स्पेन की कोच सोनिया बर्मुडेज़ ने कहा था कि उनकी टीम ड्रॉ के लिए नहीं खेलेगी, पर मैदान पर खेल उनकी बात के उलट दिखाई दिया। पहले हाफ में फ्रांज़िस्का केट का शॉट रोकने के लिए काता कॉल ने बेहद अहम सेव किया। इसके तुरंत बाद जूल ब्रांड का प्रयास आयरीन पार्डेस ने गोल लाइन पर रोक लिया। दूसरे हाफ में स्पेन के लिए एस्तेर गोंज़ालेज़ ने 52वें मिनट में पोस्ट पर गेंद मारी, जो उनकी सबसे बड़ी कोशिश रही। वहीं 71वें मिनट में ब्यूहल का शॉट भी पोस्ट से टकरा गया। अंतिम मिनटों में जर्मनी को जीत का मौका मिला था, जब जूल ब्रांड ने गेंद स्योके नुस्केन तक पहुंचाई, लेकिन काता कॉल ने बाहर आकर खतरा टाल दिया।

भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच : दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया

एजेंसी

रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले पहले वनडे मैच को लेकर शहर में उत्साह चरम पर है। दोनों टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और मैच से पहले मैदान पर जमकर पसीना बहा रही हैं।

भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी टीमों ने जेएससीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। भारत के खिलाड़ियों ने नेट्स में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में लंबा अभ्यास किया। खिलाड़ी मैच से पहले अपनी लय हासिल करने में जुटे दिखे। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका टीम ने भी अपनी रणनीति पर काम करते हुए बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ गहन अभ्यास किया। टीम इंडिया ने फुल टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और पूरी टीम नेट्स पर उतरी और करीब तीन घंटे तक अभ्यास किया। प्रैक्टिस के दौरान बल्लेबाजों ने तेज और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अलग-अलग ड्रिल्स की। विराट ने लंबे शॉट लगाकर अपनी तैयारी परखी जबकि रोहित शर्मा ने पावर-हिटिंग और स्ट्रेट बैट ड्राइव पर विशेष ध्यान दिया। भारत के बॉलिंग कोच मॉर्न मर्केल ने पत्रकारों से शुक्रवार को बातचीत करते हुए टीम की तैयारियों पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी है। कोच मर्केल ने कहा कि टीम ने टेस्ट मैच की हार को पीछे छोड़ दिया है। अब पूरा फोकस वनडे सीरीज पर है। खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और दक्षिण अफ्रीका को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। हमारा लक्ष्य इस वनडे सीरीज पर कब्जा करना है। भारतीय टीम के युवा और सीनियर खिलाड़ी दोनों ही उत्साह से भरे नजर आए। कोचिंग स्टाफ ने भी खिलाड़ियों के साथ मिलकर हर स्थिति पर काम किया।

सिक्सर्स ने लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज़ लॉरेन चीटल के साथ करार दो साल बढ़ाया

एजेंसी

सिडनी। सिडनी सिक्सर्स ने अपनी तेज गेंदबाज़ी इकाई को मज़बूती देने के लिए अपनी प्रमुख लेफ्ट-आर्म क्विक लॉरेन चीटल का करार कम से कम दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। चीटल का पिछला कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा सत्र के अंत तक था, लेकिन अब वह महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 13 तक टीम के साथ जुड़ी रहेंगी। चीटल पिछले नौ वर्षों से सिक्सर्स का हिस्सा हैं। वह 2017 में सिडनी थंडर से इस टीम में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने अपने पहले दो सत्र बिताए थे। चीटल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा, 'सिक्सर्स मेरे करियर का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं और अगले दो सत्रों के लिए टीम के साथ बने रहने पर मुझे गर्व है। मैं टीम की क्षमता पर भरोसा करती हूं और

मैजेंटा जर्सी के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं।' 27 वर्षीय चीटल डब्ल्यूबीबीएल में 100 विकेट के आंकड़े के करीब हैं। अब तक वे 93 मैचों में 95 विकेट ले चुकी हैं। सिक्सर्स के वर्तमान खिलाड़ियों में वह कप्तान एश्ले गार्डनर के बाद दूसरे स्थान पर हैं और टीम की सबसे सफल तेज गेंदबाज़ हैं। कम उम्र के बावजूद चीटल का अंतरराष्ट्रीय अनुभव काफी समृद्ध है। उन्होंने 17 साल की उम्र में 2016 में ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण किया था और उसी वर्ष टी20 विश्व कप में भी हिस्सा लिया था। वह तीनों प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी हैं। इस सीजन कप्तानी में बदलाव के बीच सिक्सर्स के लिए चीटल का यह नया करार नेतृत्व के लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण है। कंधे और पीठ की चोटों के अलावा दो बार त्वचा कैंसर का सामना करने के बावजूद चीटल ने हमेशा मजबूती से वापसी की है और कठिन परिस्थितियों में जूझने के लिए जानी जाती हैं। सिक्सर्स की जनरल मैनेजर राचेल हेन्स ने कहा, 'लॉरेन टैलेंट की मिसाल हैं। टीम में सभी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। वह शानदार आक्रामक गेंदबाज़ हैं और मैदान के अंदर व बाहर दोनों जगह नेतृत्व दिखाती हैं। ' किशोर तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर क्वीवे ब्रे और राइट-आर्मर कोर्टनी सिप्पल पहले ही टीम में हैं।

प्रीमियर लीग 2025-26: आर्सेनल के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले कोल पामर की चेल्सी में वापसी

एजेंसी

लंदन। चेल्सी के स्टार फॉरवर्ड कोल पामर इस सप्ताहांत आर्सेनल के खिलाफ होने वाले प्रीमियर लीग के शीर्ष मुकाबले में वापसी के लिए पूरी तरह फिट हैं। मैनेजर एंज़ो मारेस्का ने इसकी पुष्टि की। पामर 20 सितंबर से टीम से बाहर थे–पहले ग्रोइन इंजरी के कारण और फिर पैर की अंगुली फ्रैक्चर होने की वजह से। लगभग दो महीने बाद उनकी टीम में वापसी चेल्सी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।मारेस्का ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हर कोई खुश है, उनके साथी खिलाड़ी खुश हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोल खुद खुश हैं, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी अंत में मैदान पर उतरना ही चाहते हैं। ' पिछले सीज़न में पामर चेल्सी के टॉप स्कोरर थे, जिन्होंने प्रीमियर लीग में 15 गोल दागे थे। इस सीज़न में वे अब तक सभी प्रतियोगिताओं में

केवल चार मैच खेल पाए हैं और दो गोल किए हैं। मारेस्का ने आगे कहा, 'वह शायद हमारे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनकी वापसी से हम बेहद खुश हैं। अब ज़रूरत है उन्हें धीरे-धीरे 100% फिटनेस तक लाने की। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और हमें पूरा भरोसा है कि भविष्य में भी क्लब के लिए बेहतरीन खेल दिखाएंगे। ' वर्तमान में चेल्सी प्रीमियर लीग तालिका में दूसरे स्थान पर है, आर्सेनल से छह अंक पीछे। आर्सेनल बनाम चेल्सी का यह मुकाबला स्टैमफोर्ड ब्रिज में रविवार को खेला जाएगा।

रथयात्रा का भव्य स्वागत, खिलाड़ियों में दिखा उत्साह

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में 72वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप (पुरुष एवं महिला) के आयोजन के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रचार रथयात्रा का महाशक्ति इंटर कॉलेज, बिहसड़ा में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रथयात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से गुजरते हुए मीरजापुर पहुंची, जहां जिला ओलंपिक एवं वॉलीबॉल संघ के महासचिव एसपी त्रिपाठी के नेतृत्व में खिलाड़ियों और शिक्षकों ने अगुआनी की। कॉलेज के प्रधानाचार्य सुशील सिंह समेत शिक्षकों और छात्रों ने माला पहनाकर रथयात्रा दल का सम्मान किया। मौके पर क्षेत्र के खिलाड़ियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और उत्साहपूर्ण बना दिया। रथयात्रा का नेतृत्व कर रहे डॉ. अभिमन्यु सिंह ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और छात्र-छात्राओं को 4 जनवरी से 11 जनवरी तक सिगरा स्टेडियम, वाराणसी में होने वाली राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। संचालन जूडो संघ के सचिव अश्विनी कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी धर्मवीर सिंह, खेल एवं जन चेतना समिति के अध्यक्ष विजय सिंह, विक्रम सिंह, महेंद्र बिंद, रविंद्र प्रताप सिंह, शिखर सिंह सहित अन्य खेलप्रेमी मौजूद रहे।

इंग्लैंड को रन चेज़ के लिए तैयार रहना होगा: माइकल वॉन

एजेंसी

नई दिल्ली। डे-नाइट टेस्ट मैचों में पहले बल्लेबाजी करना जीत का 'हाईवे' माना जाता है, लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का कहना है कि ऐशेज़ को 1-1 से बराबर करने का सबसे अच्छा मौका इंग्लैंड को तभी मिलेगा जब वे गाबा में टारगेट का पीछा करें। वॉन का यह विचार इंग्लैंड की मौजूदा रणनीति और पिछले सफल परिणामों से मेल खाता है। ब्रेंडन मैकुलम के मई 2022 में कोच बनने के बाद से इंग्लैंड दो बार 350+ का लक्ष्य (373 और 378 बनाम भारत) सफलतापूर्वक चेज़ कर चुका है–ये इंग्लैंड के इतिहास की दो सबसे बड़ी सफल रन चेज़ हैं। हाल ही में इंग्लैंड 374 का पीछा करते हुए भारत से छह रन से हारा था। इसके अलावा टीम दो बार 290+ के लक्ष्य भी हासिल कर चुकी है। वॉन ने ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में कहा, 'अगर इंग्लैंड को गाबा में जीतना है तो वे अपना आक्रामक खेल ही खेलेंगे। मज़े की बात यह है कि इंग्लैंड के लिए सबसे अच्छा मौका तभी होगा जब वे टॉस हारकर लक्ष्य का पीछा करें। यह बल्लेबाजी यूनिट किसी टारगेट को देखते हुए ज्यादा बेहतर खेलती है। पहले बल्लेबाजी में वे अक्सर कंफ्यूज़ हो जाते हैं।

डे-नाइट टेस्ट में टॉस का महत्व

दुनिया में खेले गए 45 डे-नाइट टेस्ट में से 27 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। इंग्लैंड ने मैकुलम के कार्यकाल में 16 बार टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है और केवल 7 बार पहले बल्लेबाजी की है।

डे-नाइट फॉर्मेट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर जीत हासिल करने वाली अकेली टीम न्यूजीलैंड है, जिसने 2018 में ऑकलैंड टेस्ट में इंग्लैंड को हराया था। वॉन का मानना है कि गाबा में टॉस जीतकर गेंदबाजी करना बेहद जोखिम भरा कदम होगा। उन्होंने कहा,डे-नाइट मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करना ही सुरक्षित विकल्प है। यह

दिन की रोशनी में बल्लेबाजी की गारंटी देता है। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो दूसरी सुबह तक बल्लेबाजी चलती है और फिर ट्वाइलाइट में गेंदबाजी का मौका मिलता है।

इंग्लैंड की गेंदबाजी गाबा की पिच के अनुकूल

वॉन ने कहा कि इंग्लैंड के पास वह तेज गेंदबाजी आक्रमण है जो ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में बेहद घातक साबित हो सकता है। जॉफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, मार्क वुड, ब्राइडन कार्स और बेन स्टोक्स की पांच तेज गेंदबाजों वाली आक्रमक लाइन-अप ने पहले टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह झकझोरा था। उन्होंने कहा,यह इंग्लैंड की वह टीम है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया में सफल होने का सबसे अच्छा टूलसेट है। अब इतनी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास विश्वस्तरीय स्पिनर हो–ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर अब भीमातर सीमर्स के लिए काफी मदद होती है।

मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत

वॉन के अनुसार इंग्लैंड के पास नंबर 4 से 7 तक का सबसे मजबूत बैटिंग ग्रुप है–जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ। उन्होंने कहा,ये चार शायद इंग्लैंड के इतिहास के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं। बस उन्हें स्मार्ट खेलना होगा। इंग्लैंड का आक्रामक तरीका जीत दिला सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं। अगर वे थोड़ा समझदारी से खेलें तो टीम सीरीज में वापसी कर सकती है। बता दें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट 4 से 8 दिसंबर तक ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा, जो डे नाइट टेस्ट होगा।

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

एजेंसी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन कानून के कुछ नियमों का उल्लंघन करने के मामले में निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना निजी क्षेत्र के इस बैंक पर 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) से जुड़ी कानूनी और नियामकीय बाध्यताओं में कमियों के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि एचडीएफसी बैंक पर ये जुर्माना बैंक पर बैंकिंग विनियमन कानून के कुछ नियमों का उल्लंघन, कर्ज पर ब्याज दर से जुड़ी शर्तों का पालन न करने, वित्तीय सेवाओं के लिए जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के दिशानिर्देशों तथा केवाईसी से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक का निगरानी मूल्यांकन करने के लिए एक सांविधिक जांच की गई थी। बैंक को इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के जवाब और उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारियों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना आवश्यक था।

विदेशी मुद्रा भंडार 4.47 अरब डॉलर घटकर 688.1 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर झटका लगने वाली खबर है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 नवंबर को समाप्त हफ्ते में 4.47 अरब डॉलर घटकर 688.10 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.54 अरब डॉलर बढ़कर 692.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार के मूल्य में भारी गिरावट के कारण मुद्रा भंडार में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार 21 नवंबर को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.69 अरब डॉलर घटकर 560.6 अरब डॉलर रह गई। 21 नवंबर को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.47 अरब डॉलर घटकर 688.10 अरब डॉलर रहा था। आरबीआई ने बताया कि 21 नवंबर को समाप्त हफ्ते के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 2.67 अरब डॉलर घटकर 104.18 अरब डॉलर रह गया। आंकड़ों के अनुसार विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) भी 8.4 करोड़ डॉलर घटकर 18.57 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा इस सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत का आरक्षित भंडार 2.3 करोड़ डॉलर घटकर 4.76 अरब डॉलर रहा।

सरकार अक्टूबर का आईआईपी आंकड़ा अब एक दिसंबर को जारी करेगी

नई दिल्ली। औद्योगिक उत्पादन का अक्टूबर महीने का आंकड़ा एक दिसंबर को शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आमतौर पर अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का आंकड़ा हर महीने की 28 तारीख को या अगर 28 तारीख को छुट्टी होती है तो अगले कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर का आईआईपी आंकड़ा 28 नवंबर को जारी किया जाना था। चूंकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दूसरी तिमाही अनुमानों को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के साथ ही जारी किया जाना है, इसलिए अक्टूबर 2025 के अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के प्रकाशन की तारीख को पुनर्निर्धारित किया गया है।

लाल निशान पर बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 13 अंक टूटा

नई दिल्ली। वृहद-आर्थिक आंकड़े आने के पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे वाले कारोबार में लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 13.71 अंक यानी 0.016 फीसदी टूटकर 85,706.67 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 85,969.89 के ऊपरी और 85,577.82 अंक के निचले स्तर को छुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 12.60 अंक यानी 0.048 फीसदी गिरकर 26,202.95 के स्तर पर बंद हुआ है। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से पावर ग्रिड, इटर्नल, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस के शेयरों में सर्वाधिक गिरावट रही। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एशिया के अन्य शेयर बाजारों में शामिल दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग नीचे बंद हुए, जबकि जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक बढ़त में रहे। यूरोप के अधिकांश शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। एक दिन पहले गुरुवार को सेंसेक्स 110.88 अंक यानी 0.13 फीसदी उछलकर 85,720.38 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। एनएसई का निफ्टी भी कारोबार के अंत में 10.25 अंक यानी 0.039 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 के स्तर पर बंद हुआ था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है जीडीपी वृद्धि : वित्त मंत्री

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की (जुलाई-सितंबर) दूसरी तिमाही में 8.2 फीसदी की आर्थिक वृद्धि यह दर्शाती है कि सुधारों और राजकोषीय मजबूती ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ठोस वृद्धि और रफ्तार दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में कहा, विभिन्न आर्थिक संकेतक भी निरंतर आर्थिक गति और व्यापक आधार पर खपत में वृद्धि की पुष्टि करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आज जीडीपी के जारी आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत आर्थिक वृद्धि और रफ्तार दिखाते हैं। सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की (जुलाई-सितंबर) दूसरी तिमाही के लिए 8.2 फीसदी की रियल जीडीपी वृद्धि दर के साथ

भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि लगातार फिस्कल कंसोलिडेशन, इंडेक्स्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट और अलग-अलग जुटाने से हुई है, जिससे उत्पादकता मजबूत हुई है और व्यापार करने में आसानी हुई है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग हाई-फ्री म्यांमारी इंडिकेटर भी लगातार आर्थिक रफ्तार और बड़े पैमाने पर कंजम्प्शन बढ़ने की ओर इशारा करते हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस वृद्धि रफ्तार को बनाए रखने और लंबे समय तक आर्थिक वृद्धि को समर्थन करने वाले जुटाने को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है। उल्लेखनीय है कि देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही में यह वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही थी।

राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 52.59 प्रतिशत पर पहुंचा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र का राजकोषीय घाटा चालू वित्त के पहले सात महीने में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान बढ़कर 52.59 प्रतिशत पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर तक केंद्र की कुल प्राप्ति 18,00,475 करोड़ रुपये रही जबकि उसका कुल व्यय 26,25,619 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस प्रकार राजकोषीय घाटा 8,25,144 करोड़ रुपये रहा जो बजट अनुमान का 52.59 प्रतिशत है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था। सितंबर तक राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 36.53 प्रतिशत पर था। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, कुल आय में कर से प्राप्त शुद्ध आय 12,74,301 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व 4,89,079 करोड़ रुपये रहा। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां 37,095 करोड़ रुपये दर्ज की गयी। केंद्र सरकार ने करों के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को 8,34,957 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1,11,981 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्र के कुल व्यय में 20,07,876 करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 6,17,743 करोड़ रुपये पूंजी खाते में खर्च हुए। कुल राजस्व व्यय में 6,73,715 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के लिए और 2,46,575 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडियों के मद में खर्च किये गये।

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
सत्यमेव जयते

कनाडा की जीडीपी तीसरी तिमाही में 0.6 प्रतिशत बढ़ी, आयात में 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट

एजेंसी

वाशिंगटन। वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में कनाडा की वास्तविक जीडीपी 0.6 प्रतिशत बढ़ी। आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी कमी है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2025 की तीसरी तिमाही में 0.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दूसरी तिमाही में यह 0.5 प्रतिशत गिरा था। तीसरी तिमाही में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से व्यापार संतुलन में सुधार के कारण हुई क्योंकि आयात में भारी गिरावट आई और निर्यात में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई।' रिपोर्ट के अनुसार, आयात में 2.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जो चौथी तिमाही 2022 के बाद की यह सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है। इसमें कीमती धातुओं और औद्योगिक मशीनरी के आयात में सबसे ज्यादा कमी आई। दूसरी ओर, कनाडा का निर्यात थोड़ा बढ़ा। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के अनुसार, माल और सेवाओं का निर्यात तीसरी तिमाही में 0.2 प्रतिशत बढ़ा (दूसरी तिमाही में यह 7.0 प्रतिशत गिरा था)। कच्चे तेल

और क्रूड बिटुमेन के निर्यात में 6.7 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सोने, चांदी और प्लैटिनम ग्रुप धातुओं के निर्यात में कमी से कुल निर्यात वृद्धि पर कुछ असर पड़ा। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि तीसरी तिमाही में सरकार का हथियारों पर खर्च 82 प्रतिशत बढ़ गया। गैर-आवासीय संरचनाओं में निवेश के साथ मिलाकर पूंजी निवेश में कुल 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, व्यवसायों द्वारा किया जाने वाला निवेश तीसरी तिमाही में अपरिवर्तित रहा। कनाडा की अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में तकनीकी मंदी से बाहर निकलने का संकेत दिया है, लेकिन यह सुधार पूरी तरह आयात में भारी गिरावट और व्यापार संतुलन पर निर्भर रहा, घरेलू मांग और निजी निवेश अभी भी कमजोर बने हुए हैं।

नोएडा में स्टोर खोलेगी एप्पल

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल आगामी 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपना पहला और भारत में पांचवां स्टोर खोलेगी।कंपनी ने बताया कि यह स्टोर नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में खुलेगा।

यह देश में रिटेल स्टोर के विस्तार की एप्पल की योजना का हिस्सा है।फिलहाल देश में एप्पल के चार स्टोर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में हैं। एप्पल नोएडा दिल्ली-एनसीआर में कंपनी का दूसरा रिटेल स्टोर होगा। एप्पल इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि नोएडा डिजाइन और आकांक्षाओं का शहर है और नवाचार तथा मूल सोच का केंद्र है। एप्पल नोएडा में ग्राहकों के लिए कंपनी के आधुनिकतम उत्पाद उपलब्ध होंगे। इनमें आईफोन 17 सीरीज के फोन, एम5 वाले आईपैड प्रो और मैकबुक प्रो 14 शामिल हैं। वे इन उत्पादों के नये फीचरों से रू-ब-रू हो सकेंगे और

विशेषज्ञों रचनात्मक लोगों, जीनियस तथा समर्पित बिजनेस टीम से सपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। वे टूडे एट एप्पल सेशन में भी शामिल हो सकेंगे जो निःशुल्क होगा जहां फोटोग्राफी, कला, संगीत और कोडिंग के बारे में टिप्स दिये जायेंगे।कंपनी का कहना है कि ऑनलाइन एप्पल स्टोर और सेवाओं के साथ ये ऑफलाइन स्टोर भारत में एप्पल की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं।

केंद्र ने कोयला खदानों की खोज और ऑपरेशनलाइजेशन में तेजी लाने के लिए 18 मान्यता प्राप्त एजेंसियों को जोड़ा

नई दिल्ली। देश में कोयला खनन को रफ्तार देने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश में मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के दायरे को बढ़ाते हुए निजी संस्थाओं को भी अधिकृत एजेंसियों की सूची में 18 मान्यता प्राप्त एजेंसियों को शामिल किया गया है। कोयला मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि कोयला खदानों की खोज में तेजी लाने और उन्हें जल्दी चालू करने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए 18 और प्राइवेट कंपनियों को एक्रेडिटेड प्रॉस्पेक्टिंग एजेंसी (एपीए) के तौर पर नोटिफाई किया गया है। इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट httpsÑ//coal.nic.in/sites/default/files/2025-11/28-11-2025a-wn.pdf पर उपलब्ध है। मंत्रालय की ओर से 26 नवंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार खान व खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के दूसरे प्रावधान के तहत, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की नेबेट (QCI-NABET) द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को आधिकारिक रूप से खनिज खोज संबंधी कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इससे कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए 18 और एजेंसियां जुड़ जाएंगी, जिससे कोयला ब्लॉक आवंटियों को कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए इन एजेंसियों को नियुक्त करने में अधिक विकल्प मिलेगा।

नई मान्यता प्राप्त एजेंसियों में ये हैं शामिलः- इंडियन माइन प्लानिंग एंड कंसल्टेंट्स, कोलकाता; मेरॉक्स माइनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम; यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता; माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता; नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन - टाटा स्टील लिमिटेड, पूर्वी सिंहभूम; माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बिदवान; रेम्को कोल एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रपुर; साउथ वेस्ट जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम; जियोटेक्निकल माइनिंग सॉल्यूशंस, धर्मपुरी; नोवोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ईस्ट खासी हिल्स; सुरमाइन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली; कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर; माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद; जेम्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रांची; रेवेल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद; सीएमएमसीओ टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, हैदराबाद; जसनी जियोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर; एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, नामक्कल शामिल हैं। कोयला मंत्रालय ने कहा कि इन अन्वेषण एजेंसियों के जुड़ने से लगभग 6 महीने का समय बचेगा, जो पहले एजेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने में लगता था। अधिकृत संभावित एजेंसियों के समूह का विस्तार करके, सरकार निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना और अन्वेषण में दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहती है। उम्मीद है कि इस कदम से अन्वेषण की गति में काफी तेजी आएगी और खनन को जल्दी बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे संसाधन विकास में तेजी आएगी और देश के लिए कोयला और लिग्नाइट की उपलब्धता बढ़ेगी।

ट्रेड फेयर में टपन एग्रो कम्पनी के उत्पादों ने दर्शको को लुभाया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान के हॉल नं0 12ए स्टाल नं0 12 पर टपन एग्रो इंडस्ट्रिज प्रा0लि0 आगरा का स्टॉल आप गृहणियों व जनता का आर्कषर्ण व जिज्ञासा का केन्द्र बना हुआ है । कम्पनी के जी0एस0सेल्स मनोज शर्मा ने बताया कि हमारी कम्पनी का कुकिंग मीडियम दीप और प्रीत लाईट, प्रीत लाईट गोल्ड व डे लाईट कच्ची धानी, फलोशियों आलिव ऑयल प्योरनैस नारियल का तेल आदि प्रोडक्टस स्टाल पर लगाया व कम्पनी के प्रोडक्टस से बना माल आने वाले दर्शको को खिलाया और आम जनता को व्यापार मेले मे बहुत पसन्द आ रहा है और काफी मात्रा मे

प्रोडक्टस की खरीदारी भी की है। मनोज शर्मा के अनुसार हमारे उत्पाद प्रीत लाईट गोल्ड कल्सट्रोल फ्री है जिस के खाने से मोटापा नहीं बढ़ता और खाने मे हल्कापन रहता है हमारी कम्पनी का उत्पाद मसकट, दुबई साऊदी अरब, यू.ए.ई. कतर, बहरीन औमान, सिंगापुर, आस्ट्रेलियां, हाँग कोंग, थाईलैण्ड आदि विदेशो मे निर्यात हो रहा है और शीघ्र ही अमेरिका व यूरोप निर्यात करने योजना बना रही है इसके इलावा भारत के सभी राज्यों मे आसानी से उपलब्ध है और हमारा प्रोडक्टस आन लाईन पर भी उपलब्ध है।

एसुस जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर नोटबुक कंपनी रही

एजेंसी

नई दिल्ली। ताइवान की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी एसुस इंडिया ने वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए भारत में कंज्यूमर नोटबुक कंपनी के रूप में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आईडीसी क्वार्टरली पर्सनल कम्प्यूटिंग डिवाइस ट्रैकर, 2025 क्यू3 की रैंकिंग में उसने यह उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस बात से स्पष्ट है कि एसुस हर साल उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है। यह वृद्धि ब्रांड के प्रति ग्राहकों के भरोसे को बनाये रखने, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार और देश के 600 से अधिक जिलों में खुदरा टचपॉइंट्स बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि

एसुस इंडिया ने एसुस एआई पीसी, कंज्यूमर और गेमिंग नोटबुक्स के साथ-साथ एआईओ, डेस्कटॉप और एक्सेसरीज़ श्रेणियों में महत्वपूर्ण नवाचार पेश किये हैं। इस साल कंपनी ने मल्टी-कलर विवोबुक, आरओजी एली एक्स और कई सफल अभियानों की शुरुआत की जो काफी लोकप्रिय हुए। एआईओ सेग्मेंट में भी इसने बाजार में दबदबा बनाये रखा और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद में शामिल रहा।

एसुस इंडिया ने सबसे हल्का कोपायलट प्लस पीसी, आरओजी एली ज़ेनबुक ए14 लॉन्च किया और भारत में एनवीडिया आरटीएक्स 5000 सीरीज़ में नंबर एक बाजार हिस्सेदारी हासिल की।

एसुस इंडिया के उपाध्यक्ष अर्नोल्ड सू ने कहा कि साल 2025 की शुरुआत से ही कंपनी भारत में खुद को ऐसे पीसी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है जो टेक्नोलॉजी के जरिये ग्राहकों के लिए सुविधा लाये। उन्होंने बताया कि कंपनी ने कंज्यूमर नोटबुक पीसी श्रेणी में सालाना सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और अब इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।

इंडिगो नवी मुंबई से कोयंबटूर, चेन्नई और वड़ोदरा के लिए शुरू करेगी उड़ानें

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू यात्री संख्या के मामले में देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने शनिवार को नवी मुंबई एयरपोर्ट से अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि नवी मुंबई हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 08 अक्टूबर को किया था।

वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन 25 दिसंबर से शुरू होगा। इंडिगो ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वह 26 दिसंबर से नवी मुंबई से उत्तरी गोवा (मोपा) के लिए उड़ान सेवा शुरू करेगी जो सोमवार और गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन उपलब्ध होगी। इसके बाद 29 दिसंबर से कोयंबटूर और चेन्नई के लिए दैनिक उड़ानें शुरू की जायेंगी। नवी मुंबई के वड़ोदरा के लिए 30 दिसंबर से उड़ान शुरू होगी जो सप्ताह में पांच दिन - मंगलवार,

बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार - को उपलब्ध होगी। इनमें गोवा के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई गयी है जबकि अन्य मार्गों पर नयी उड़ानें शुरू की जा रही हैं। एयरलाइंस ने पहले बताया था कि वह नवी मुंबई से 10 शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, उत्तरी गोवा (मोपा), जयपुर, नागपुर, कोचिन और मेंगलुरु के लिए उड़ानें शुरू करेगी।

विवेक चतुर्वेदी होंगे सीबीआईसी के नए चेयरमैन, सरकार ने दी मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। वह संजय कुमार अग्रवाल की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक

आदेश के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विवेक चतुर्वेदी की सीबीआईसी के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विवेक चतुर्वेदी 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य हैं। चतुर्वेदी सीबीआईसी के सदस्य बनने से पहले विभाग में प्रधान महानिदेशक 'विजिलेंस' थे। वह अभी सीबीआईसी बोर्ड (टैक्स पॉलिसी और लीगल) के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। वे इस साल अगस्त में विवेक रंजन के सेवानिवृत्त होने के बाद बोर्ड में शामिल हुए। उन्होंने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और उनके पास जांच कार्यों का अच्छा-खासा अनुभव है।

डिलीवरी पार्टनर्स को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जोमैटो और ब्लिंकिट ने दिल्ली में लगाए शिविर

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत की अग्रणी फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तीसरा 'सरकारी योजना सुविधा शिविर' लगाया। इस पहल का उद्देश्य डिलीवरी पार्टनर्स को केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं तक सरल, सुव्यवस्थित और प्रभावी पहुंच उपलब्ध कराना है।

जोमैटो और ब्लिंकिट शिविरों में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उप-सचिव मिनहाज अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बेंगलुरु और मुंबई में आयोजित शिविरों के बाद दिल्ली के इस ऑन-ग्राउंड शिविर में भी 340 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स को संबंधित केंद्र और राज्य योजनाओं में नामांकन कराने में सहायता मिली। डिलीवरी पार्टनर्स ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (स्वास्थ्य बीमा), राशन कार्ड, ई-श्रम (असंगठित श्रमिकों का केंद्रीकृत डेटाबेस), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (जीवन बीमा), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) और 'कर्नाटक स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम' जैसी योजनाओं में अधिक रुचि दिखाई है।

मनहाज अहमद ने कहा कि जोमैटो और ब्लिंकिट की यह पहल डिलीवरी पार्टनर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना तथा ई-श्रम जैसे अहम पोर्टल तक पहुंच उपलब्ध कराने में सक्षम बना रही है, जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ऐसे शिविर अधिक परिवारों तक वह सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देशभर में और अधिक डिलीवरी पार्टनर्स इन योजनाओं से जुड़कर पंजीकृत होते रहेंगे। कार्यक्रम में ईटरनल के चीफ

सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अंजली रवि कुमार ने कहा कि डिलीवरी पार्टनर्स का कल्याण हमेशा से ईटरनल के हर प्रयास का केंद्र रहा है। यह सरकारी योजना सुविधा शिविर डिलीवरी पार्टनर्स और उन सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। हम अपने पार्टनर के साथ मिलकर लगातार अपने आउटरीच प्रयासों को सीख रहे हैं और उन्हें बेहतर बना रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से जोमैटो की डिलीवरी पार्टनर उमावती ने कहा कि मैं आयुष्मान भारत, पेंशन और ई-श्रम कार्ड जैसे लाभों के लिए आसानी से पंजीकरण कर पाई। ये लाभ मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे और इन्होंने मुझे सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा दिया है। जोमैटो और ब्लिंकिट के शिविर ने पूरी प्रक्रिया को बहुत सरल और समझने में आसान बना दिया। हकदारशक के वाइस प्रेसिडेंट (प्रोडक्ट) मनोज जोशी ने कहा कि जोमैटो और ब्लिंकिट के साथ हमारा सहयोग कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हक़दारशक के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और पात्रता जांच इंजन के माध्यम से हम तकनीक और मानवीय सहायता को जोड़कर डिलीवरी पार्टनर्स के लिए लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा तेज़ बना रहे हैं। हमने पाया है कि डिलीवरी पार्टनर्स ऐसा समग्र सुरक्षा कवरेज चाहते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा का संयुक्त लाभ शामिल हो।

पाकिस्तान में मुनीर ने संभाला सीडीएफ का भार

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने आधिकारिक रूप से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) का पद संभाल लिया है। साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) का भी पद संभाल लिया है। पाकिस्तान के संविधान में विवादित 27वें संशोधन के ज़रिए बनाया गया यह पद श्री मुनीर को पांच साल के तय समय के लिए तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना का प्रमुख बनाता है। यह बदलाव सभी आधिकारिक दस्तावेजों, सैन्य बलों और मीडिया रिपोर्ट्स में दिखेगा। संविधान के 27वें संशोधन का मकसद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएसी) का पद खत्म करना है। अब उसकी जगह कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ले लेगा। प्रधानमंत्री सीओएएस /सीडीएफ की सिफारिशों के आधार पर तीन साल के समय के लिए पाकिस्तान सेना के मौजूदा जनरलों में से कमांडर को नियुक्त करेंगे। जनरल (सेवानिवृत्त) साहिर शमशाद मिर्ज़ा जॉइंट चीफ्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी के चेयरमैन का टाइटल रखने वाले पाकिस्तान के आखिरी अधिकारी रहे। वह बुधवार को इस पद से सेवानिवृत्त हो गये।सीडीएफ के मुख्य कामों मेंबहु-डोमेन एकीकरण, पुनर्गठन और पाकिस्तान की सशस्त्र बलों में मज़बूत समन्वय स्थापित करना है।

बाइडेन के 'ऑटोपेन' से साइन हुए 92फीसदी ऑर्डर रद्द

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 'ऑटोपेन' से साइन किए गए सभी दस्तावेजों को रद्द कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि बाइडेन के लगभग 92फीसदी ऑर्डर इसी मशीन से हस्ताक्षरित थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और विवादित कदम उठाया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 'ऑटोपेन' मशीन से साइन किए गए सभी दस्तावेजों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे बाइडेन के कथित तौर पर नियंत्रण खोने और स्टाफ पर अत्यधिक निर्भरता को मुख्य वजह बताया है। इस ऐलान के बाद, अमेरिका में राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है।

इंडिगो नवी मुंबई से कोयंबटूर, चेन्नई और वड़ोदरा के लिए शुरू करेगी उड़ानें

नई दिल्ली। घरेलू यात्री संख्या के मामले में देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने शनिवार को नवी मुंबई एयरपोर्ट से अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि नवी मुंबई हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 08 अक्टूबर को किया था। वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन 25 दिसंबर से शुरू होगा। इंडिगो ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वह 26 दिसंबर से नवी मुंबई से उत्तरी गोवा (मोपा) के लिए उड़ान सेवा शुरू करेगी जो सोमवार और छोड़कर सप्ताह में पांच दिन उपलब्ध होगी। इसके बाद 29 दिसंबर से कोयंबटूर और चेन्नई के लिए दैनिक उड़ानें शुरू की जायेंगी। नवी मुंबई के वड़ोदरा के लिए 30 दिसंबर से उड़ान शुरू होगी जो सप्ताह में पांच दिन - मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार - को उपलब्ध होगी। इनमें गोवा के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई गयी है जबकि अन्य मार्गों पर नयी उड़ानें शुरू की जा रही हैं। एयरलाइंस ने पहले बताया था कि वह नवी मुंबई से 10 शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, उत्तरी गोवा (मोपा), जयपुर, नागपुर, कोचिन और मेंगलुरु के लिए उड़ानें शुरू करेगी।

ट्रंप ने हमले की धमकी के बीच मादुरो से की फोन पर बात, वेनेजुएला संकट में नई कूटनीति शुरू, आमने-सामने बैठक की संभावना पर चर्चा

नई दिल्ली। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकियों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के बीच एक अप्रत्याशित फोन बातचीत हुई है। यह उच्च-स्तरीय संपर्क वाशिंगटन और कराकस के बीच वर्षों के तनाव के बाद हुआ है। इस बातचीत को मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए राजनयिक मार्ग अपनाने के अमेरिकी इरादे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, पिछले सप्ताह के अंत में हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भविष्य में अमेरिका में आमने-सामने की बैठक की संभावना पर भी चर्चा की। यह संपर्क सालों में किया गया पहला सीधा संपर्क है। यह संकेत देता है कि अमेरिका, सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह के दबाव का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मादुरो को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। फोन पर बातचीत के बावजूद, ट्रंप प्रशासन की तरफ से वेनेजुएला पर संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना के संकेत लगातार मिल रहे हैं। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के कथित 'कार्टेल ऑफ द सन्स' को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिसका नेतृत्व मादुरो पर करने का आरोप है। मादुरो ने हमेशा ड्रग तस्करी के आरोपों से इनकार किया है और झुकने से मना किया है।

इमरान खान को लेकर सुलगा पाकिस्तान

PTI समेत विपक्षी गठबंधन ने देशभर में दी प्रदर्शन की चेतावनी

एजेंसी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अदियाला जेल में हत्या की अफवाह उड़ने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बहन अलीमा खान लगातार शहबाज सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें इमरान से मिलने दिया जाए। विपक्षी गठबंधन ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन ने बताया कि पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (पीकेएमएपी) के अध्यक्ष महमूद अचकजई ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चेतावनी जारी की है। अचकजई ने दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमने सिंधियों, बलूचों, पश्तूनों और पंजाबियों को सरकार और उनकी

नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने से रोक दिया है। नहीं तो, वे बाहर आकर शासकों के लिए समस्या खड़ी कर देते।' उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद को रबर स्टांप बना दिया है और नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक कहीं और से हुक्म सुन रहे हैं। ट्राइबल इलाकों में लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी स्पीकर ने विपक्ष को इस गंभीर मुद्दे पर बोलने नहीं दिया। पाकिस्तानी सरकार को घेरते हुए उन्होंने पूछा कि इमरान खान को जेल में क्यों रखा गया है और उन्हें अपनी बहन और पार्टी लीडर्स से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अदियाला जेल के बाहर बैठे हैं, लेकिन पीटीआई के फाउंडर से मिलने की उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ' पीटीआई नेता असद कैसर ने कहा कि हाल के उपचुनावों में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया। हरिपुर में हुए उपचुनाव के नतीजे बदल दिए गए थे। यहां से पूर्व विपक्षी नेता उमर अयूब की पत्नी चुनाव लड़ रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया, 'फॉर्म 47 पर जो नतीजा था, वह कंप्यूटर पर बदले गए नतीजे से अलग था। ' ठीक एक दिन पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक्स पर पोस्ट करके अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा था। इसके साथ ही कासिम ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और इंटरनेशनल कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।

ताइवान पर जापान की प्रधानमंत्री की टिप्पणी गलत - माओ निंग

एजेंसी

बीजिंग। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु ताकाइची की ताइवान संबंधी टिप्पणियां 'ताइवान की स्वतंत्रता' चाहने वाली अलगावादी ताकतों को बहुत गलत संकेत देती हैं। साथ ही उन्होंने ताइवान के नेता लाई चिंग-ते द्वारा जापान के समर्थन में किए गए प्रयास की भी कड़ी आलोचना की। सुश्री शिगेरु ताकाइची की उस टिप्पणी में ताइवान जलडमरूमध्य में सशस्त्र हस्तक्षेप की संभावना का इशारा किया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय और जापान के समझदार लोगों ने भी निंदा की है। इसके बावजूद श्री लाई चिंग-ते ने जापान के प्रति समर्थन दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे जापानी सीफूड से बनी सुशी पकड़े दिखाई दे रहे थे।

सुश्री माओ निंग ने कहा, 'जापान ने आधी सदी तक ताइवान पर औपनिवेशिक शासन किया और वहां अनगिनत अत्याचार किए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) के अधिकारियों का तथाकथित 'ताइवान स्वतंत्रता' के लिए जापान को मनाने की कोशिश करना बेहद नीच और शर्मनाक है। '

उन्होंने आगे कहा कि सुश्री ताकाइची का ताइवान संबंधी बयान चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, यह 'ताइवान स्वतंत्रता' की अलगावादी ताकतों को गलत संदेश देता है तथा ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता को खतरे में डालता है।

प्रवक्ता ने याद दिलाया कि इस वर्ष जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जनता के प्रतिरोध युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ तथा ताइवान के चीन में पुनः एकीकरण की 80वीं वर्षगांठ है।

गोलीकांड के बाद अमेरिका सख्त, अफगानिस्तान के लोगों के वीजा पर लगाई रोक

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई गोलीबारी में एक महिला सैनिक की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने जानकारी दी है कि अमेरिका ने अफगान वीजा पर रोक लगा दी है। इसी सप्ताह अफगानिस्तान के एक शख्स ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की, जिसमें दो नेशनल गार्ड्स बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के दौरान एक महिला सैनिक की मौत हो गई और दूसरे का इलाज जारी है। मार्को रुबियो ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश विभाग ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। अमेरिका के लिए हमारे देश और हमारे लोगों की सुरक्षा से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं है। ' अमेरिकी एजेंसी ने एक बयान में कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने

वाले लोगों के लिए वीजा जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी है। ' गोलीबारी की घटना में 29 साल के संदिग्ध रहमानुल्लाह लकनवाल का नाम सामने आया है। अमेरिकी फोर्स ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोलीबारी के दौरान अमेरिकी फोर्स की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में लकनवाल घायल हो गया था। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि शख्स पूर्व की जो बाइडेन सरकार के कार्यकाल में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 2021 में अमेरिका आया था। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शूटर ने पिछले साल अमेरिका में शरण के लिए आवेदन दिया था और इस साल की शुरुआत में उसे इसकी स्वीकृति मिल गई थी।अमेरिका की एफबीआई एजेंसी इस गोलीबारी की घटना की जांच आतंकवाद के एक एक्ट के तहत कर रही है। लकनवाल पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्स के साथ काम कर चुका था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तानी लोगों के माइग्रेशन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन हमेशा के लिए रोकने की तैयारी कर रहे हैं।

अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगाई

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता का हवाला देते हुए अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई उस घटना के बाद की गई है जिसमें एक अफगान नागरिक ने 26 नवंबर को व्हाइट हाउस से पास दो गार्ड्स को गोली मार दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। अपने लोगों की सुरक्षा अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि एक अफगान नागरिक

ने 26 नवंबर को व्हाइट हाउस से पास दो गार्ड्स को गोली मार दी थी। जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा कर दी कि अमेरिकी प्रशासन तीसरी दुनिया से आने वाले प्रवासियों पर स्थायी प्रतिबंध लागू करेगा, ताकि अमेरिकी व्यवस्था को पूरी तरह पुनर्स्थापित होने के लिए समय मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका देश के अंदर मौजूद गैर-नागरिकों को दिए जाने वाले संघीय लाभ और सब्सिडी बंद कर देगा।

श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वा से तबाही, अबतक 69 लोगों की मौत, काफी संख्या में लोग लापता

एजेंसी

कोलंबो। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वा से भारी तबाही हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण अलग-अलग हिस्सों में स्थिति गंभीर हो गई है।इस आपदा से मरने वालों की संख्या 69 तक पहुंच गई है जबकि काफी संख्या में लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।इस दौरान कई पुल और सड़कों के बह जाने से स्थिति खराब हुई है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अधिसूचना जारी कर महत्वपूर्ण सेवाओं बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और गैस, अस्पताल और जलापूर्ति को आवश्यक सेवाएँ घोषित किया है।

डेली मिरर ने मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि श्रीलंका में लगातार बना निम्न-दाब तंत्र स्थिर बना हुआ है, जिससे नमी वाली हवाएँ आ रही हैं और बार-बार तीव्र लहरें उठ रही हैं। लगातार मूसलाधार

बारिश से तमाम प्रमुख जलाशय भर गए हैं। मोरागहाकांडा जलाशय अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुँच गया जिसके बाद इसके स्पिल गेट खोल दिए गए और इसी दौरान मोरागहाकांडा-लग्गाला का विशाल पुल ढह गया। यह पुल मटाले, पोलोन्नारुवा और कुरुनेगला जिलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता था। इसी तरह हसलाका क्षेत्र में याहंगला पर्वत के पास हुए भीषण भूस्खलन के बाद 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। देश के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं की आशंका कम नहीं हुई है। आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) के अनुसार, 16 नवंबर से शुरू हुई आपदा ने अबतक देशभर के 63,000 से ज़्यादा परिवारों के 2,19,286 लोगों को प्रभावित किया है। इस आपदा में अबतक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग से अधिक लापता हैं। सरकार ने घोषणा की है कि विदेशों में रहने वाले श्रीलंकाई और विदेशी नागरिक राहत कार्यों में योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग ने कहा कि निर्दिष्ट बैंक खाते का विवरण विदेशों में श्रीलंकाई राजनयिक मिशनों और श्रीलंका स्थित विदेशी मिशनों में उपलब्ध है।

भारतीय राजदूत से मिलीं नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सहयोग पर हुई गहन चर्चा

एजेंसी

काठमांडू। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री डॉ. सुधा शर्मा गौतम और नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के बीच औपचारिक

मुलाक़ात हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और अतुलनीय मित्रता पर जोर देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूद द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत, टिकाऊ और प्रभावकारी बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री गौतम ने भारत की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल-भारत के संबंध गहरे और विश्वासपूर्ण हैं। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय औषध प्रयोगशाला की परीक्षण क्षमता वृद्धि तथा विदेशों में कार्यरत नेपाली श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में बताया।

राजदूत श्रीवास्तव ने भारत-नेपाल संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय औषध प्रयोगशाला के स्तरोन्नयन के लिए भवन निर्माण, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने और प्रशिक्षित मानव संसाधन विकास में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री कार्की ने सैन्य मुख्यालय पहुंचकर चुनावी सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा

एजेंसी

काठमांडू। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाली सेना के मुख्यालय जंगी अड्डा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। नेपाली सेना ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति, प्रमुख चुनौतियों और आगे की रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही चुनावी सुरक्षा में सेना की तैनाती की योजना और उसकी रूपरेखा भी साझा की गई। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि जेन-जी आंदोलन के बाद बनी इस सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी शांति एवं सुरक्षा स्थापित कर आगामी फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना है। उन्होंने सेना पर विश्वास जताते हुए कहा कि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव

सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जनता की सुरक्षा की गारंटी, पुलिस कार्रवाई को सुचारू और सुरक्षित बनाने तथा सभी राजनीतिक गतिविधियों को बिना अवरोध संचालित करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ा जाए। कार्की ने कहा कि आने वाले चुनाव में एक बूंद भी खून नहीं बहना चाहिए और न ही कोई घायल होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि पिछले चुनावी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी सुरक्षा निकायों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में त्रुटिरहित काम किया जाए। साथ ही जेन-जी आंदोलन के दौरान लूटे गए और लापता हथियारों की खोज और नियंत्रण में तथा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस का पूरा सहयोग किया जाए।

इस मौके पर गृह मंत्री ओमप्रकाश अर्याल, कानून मंत्री अनिल कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नेपाल के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार गठन का किया बचाव, लिखित जवाब दाखिल

एजेंसी

काठमांडू। प्रतिनिधि सभा विघटन और सर्वोच्च अदालत की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी सरकार का बचाव करते हुए राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने सर्वोच्च अदालत में लिखित जवाब दाखिल किया है। राष्ट्रपति ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि संवैधानिक इजलास में विचाराधीन सभी 17 रिट खारिज की जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि जेन-जी आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार गठन करने की संवैधानिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति के समक्ष आई थी और तत्कालीन बाध्यकारी परिस्थिति के कारण काक राष्ट्रपति का दावा है कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना की मांग वर्तमान संवैधानिक और राजनीतिक परिस्थिति के अनुरूप नहीं है और इसलिए रिट खारिज किए जाने योग्य है। जवाब में कहा गया है

कि उस समय प्रधानमंत्री पद रिक्त था और राजनीतिक दल सरकार गठन के लिए आगे नहीं आ पा रहे थे, जिससे देश की शांति, सुरक्षा और शासन व्यवस्था पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। जवाब के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश के आधार पर संविधान में निहित राष्ट्र प्रमुख के अधिकारों का प्रयोग करते हुए असाधारण परिस्थिति का समाधान करने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया।

खालिदा जिया की हालत बेहद गंभीरः बीएनपी की राष्ट्रव्यापी प्रार्थना की अपील

एजेंसी

ढाका। बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया (79) का स्वास्थ्य बिगड़कर 'बेहद गंभीर' स्थिति में पहुँच गया है। यह जानकारी उनकी पार्टी बंगलादेश नेशलिस्ट पार्टी

(बीएनपी) महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने दी है। उन्होंने पूरे देश से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि बेगम जिया को 23 नवंबर की देर रात एवरकेयर अस्पताल के कोरोनरी केयर यूनिट (सीसीयू) में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञों वाले एक मेडिकल बोर्ड की गहन निगरानी में चल रहा है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उनकी हालत गुरुवार रात से और खराब हुई है, और उनके दिल और फेफड़ों दोनों में संक्रमण फैल गया है। बीएनपी नेता आलमगीर ने कहा कि लोकतंत्र के लिए उनके लंबे संघर्ष ने उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। उनकी बिगड़ती हालत ने पार्टी नेताओं और समर्थकों को चिंतित कर दिया है।

हांगकांग की आठ आवासीय इमारतों में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हुई, अधिकांश की पहचान असंभव

एजेंसी

हांगकांग। दुनिया में अपनी निराली चमक और दमक के लिए विख्यात और 24 घंटे पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ता हांगकांग अपने इतिहास की सबसे बड़ी आग त्रासदी से जूझ रहा है। परसों (26 नवंबर) आठ बहुमंजिला आवासीय इमारतों (टॉवर्स) में लगी आग में जनहानि के आंकड़ों को सुनकर लोग दहल गए। अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकांश के शव की पहचान करना असंभव है।हांगकांग में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले द स्टैंडर्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग के शीर्ष अधिकारियों ने आज दोपहर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज तड़के घटनास्थल से पांच शव और मिले। इनमें दो शव बच्चों के थे। दोपहर होते-होते मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 से 128 हो गई। बचाव टीमें अभी भी जीवित लोगों की तलाश में धधक रहे टॉवर्स का चप्पा-चप्पा छान रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से चार इमारतों की आग गुरुवार रात तक बुझाई जा चुकी थी। तीन इमारतों में दमकल

विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्कत कर रहे थे। एक टॉवर को सुरक्षित बताया गया था। बचाव अभियान की आखिरी कोशिशों के बीच आज तड़के आग फिर भड़क गई और इलाका धुआं से भर गया। आग की चपेट में आए यह सभी टॉवर्स 'ताई पो के वांग फुक कोर्ट' क्षेत्र में हैं।

हांगकांग के सुरक्षा सचिव क्रिस टैंग पिंग-क्यूंग ने संवाददाता सम्मेलन में आशंका जताई कि अभी भी सुलगती बिल्डिंग्स के अंदर और भी लोग मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 108 शव मिले हैं। इनमें 16 शव अभी भी टॉवर्स में फंसे हुए हैं। बचाए गए लोगों में से चार की सांसें अस्पतालों में थम गईं। द स्टैंडर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक सिर्फ 39 लोगों की ही आधिकारिक पहचान हो सकी है। टैंग ने कहा कि आग लगने के बाद से 467 लोगों के गुम होने की सूचना मिली है। इनमें से कुछ लोगों के अलग-अलग रिश्तेदारों ने अपने एक ही परिजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसलिए लापता लोगों की संख्या कुछ कम हो सकती है। इस समय अस्पतालों में सिर्फ 79 लोग भर्ती हैं। सभी का इलाज चल रहा है। इन आठ टॉवर्स में करीब 2,000 फ्लैट हैं। अधिकारियों ने कल बताया था कि इस संबंध में भवन निर्माण कंपनी के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो निदेशक और एक सलाहकार अभियंता है। स्वास्थ्य सचिव लो चुंग-माऊ का कहना है कि इस त्रासदी में बहुत से लोगों की मौत धुआं में दम घुटने से भी हुई है। गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

page 1 and 8_page 1 Mar 25 final ds.qxd 11/30/2025 12:00 AM Page 2

कुदरत के दिये गये वरदानों में पेड़-पौधों का महत्वपूर्ण स्थान

कुदरत के दिये गये वरदानों में पेड़-पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़-पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ती ही होती बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं-कार्बन चक्र हो या भोजना श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है।

हमारे शरीर को निरोगी बनाये रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी-बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचायी बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अमल में लाया जाता है।

यही नहीं, जंगलों में खुद-ब-खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा-अर्चना तक की जाने लगी है जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिध्द विद्वान चरक ने तो हरेक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है।

औषधीय पेड़-पौधे,जड़ी-बूटियां और उनके वानस्पतिक नाम

1. नीम- एक चिपरिचित पेड़ है जो 20 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है इसकी एक टहनी में करीब 9-12 पत्ते पाए जाते है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसका पत्ता हरा होता है जो पक्व कर हल्का पीला-हरा होता है। अक्सर ये लोगो के घरों के

आस-पास देखा जाता है।

2. तुलसी- तुलसी एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके फूल गुच्छेदार तथा बैंगनी रंग के होते हैं तथा इसके बीज घुटलीनुमा होते है। इसे लोग अपने आंगन में लगाते हैं ।

3. ब्राम्ही/ बेंग साग- यह साग पानी की प्रचुरता में सालो भर हरी भरी रहने वाली छोटी लता है जो अक्सर तालाब या खेत माय किनारे पायी जाती है। इसके पत्ते गुदे के आकार (1/2 -2 इंच) के होते हैं। यह हरी चटनी के रूप में आदिवासी समाज में प्रचलित है ।

4. ब्राम्ही- यह अत्यंत उपयोगी एवं गुणकारी पौधा है । यह लता के रूप में जमीन में फैलता है। इसके कोमल तने 1-3 फीट लम्बी और थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होती है। इन गांठो से जड़े निकलकर जमीन में चली जाती है। पत्ते छोटे,लम्ब,अंडाकार,चिकने,मोटे हरे रंग के तथा छोटे-छोटे होते हैं सफ़ेद हल्के नीले गुलाबी रंग लिए फूल होते हैं। यह नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं ।

5 .हल्दी- हल्दी के खेतों में तथा बगान में भी लगया जाता है। इसके पत्ते हरे रंग के दीर्घाकार होते हैं।इसका जड़ उपयोग में लाया जाता है। कच्चे हल्दी के रूप में यह सौन्दर्यवर्द्धक है।सुखे हल्दी को लोग मसले के रूप में इस्तेमाल करे हैं। हल्दी रक्तशोधक और काफ नाशक है ।

6. चिरायता / भुईनीम- छोटानागपुर के जगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 1-3 फीट तथा उसकी अनेक शाखाएँ पतली-पतली होती है। इसकी पत्तियां नुकीली, भालाकर, 3-4 इंच लम्बी तथा एक से सवा इंच चौड़ी होती है। फूल छोटे हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग के होते हैं यह बरसात के दिनों में पनपता है और जाड़े में फल तथा फूल लगते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है ।

7. अड़ूसा- यह भारत के प्रायः सभी क्षेत्रो में पाया जाता है। यह सालों भर हरा भरा रहनेवाला झाड़ीनुमा पौधा है जो पुराना होने पर 8-10 फीट तक बढ़ सकता है।इसकी गहरे हरे रंग की पत्तियां 4-8 इंच लम्बी और 1-3 इंच चौड़ी है। शरद ऋतू के मौसम में इसके अग्र भागों के गुच्छों में हल्का गुलाबीपन लिए सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं।

8. सदाबहार- यह एक छोटा पौधा है जो विशेष देखभाल के बिना भी रहता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अपना महत्त्व है। इसकी कुछ टहनियां होती है और यह 50 सेंटी मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके फूल सफ़ेद या बैगनी मिश्रित गुलाबी होते हैं।यह अक्सर बगान, बलुआही क्षेत्रो, घेरों के रूप में भी लगया जाता है ।

9. सहिजन / मुनगा- सहिजन एक लोकप्रिय पेड़ है।जिसकी ऊंचाई 10 मीटर या अधिक होती है । इसके छालों में लसलसा गोंद पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे और गोल होते हैं तथा फूल सफेद होते हैं।इसके फूल पत्ते और फल (जोकी) खाने में इस्तेमाल में लाये जाते हैं। इसके पत्ते (लौह) आयरन के प्रमुख स्रोत हैं जो गर्भवती माताओं के लिए लाभदायक है ।

10. हडजोरा

10.1. Tinospora cordifolia- हड्जोरा /अमृता एक लता है।इसके पत्ते गहरे हरे रंग के तथा हृदयाकार होते हैं। मटर के दानो के आकार के इसके फल कच्चे में हरे तथा पकने पर गहरे लाल रंग होते हैं।यह लता पेड़ों , चाहरदीवारी या घरों के छतों पर आसानी से फैलती है।इसके तने से पतली पतली जड़ें निकल कर लटकती है ।

10.2. Vitis quadrangularis- हडजोरा का यह प्रकार गहरे हरे रंग में पाया जाता है।ये गुठलीदार तथा थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठे होती है।इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं।जोड़ों के दर्द तथा हड्डी के टूटने तथा मोच आने पर इसका इस्तेमाल किये जाने के कारण इसे हडजोरा के नाम से जाना जाता है ।

11. करीपत्ता- करीपत्ता का पेड़ दक्षिण भारत में प्रायः सभी घरों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्यता भोजन में सुगंध के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। इसके पत्तों का सुगंध बहुत तेज़ होता है। इसकी छाल गहरे धूसर रंग के होती है इसके पत्ते अंडाकार, चमकीले और हरे रंग के होते हैं।इसके फूल सफ़ेद होते हैं एवं गुच्छेदार होते हैं।इसके फल गहरे लाल होते हैं जो बाद में बैगनी मिश्रित कालापन लिए होता है ।

12. दूधिया घास- यह साधरणतः खेतों, खलिहानों, मैदानों में घासों के साथ पाया जाता है। इसके फूल बहुत छोटे होते हैं जो पत्तों के बीच होते हैं। यह स्वाद में कडुवा होता है। इसकी छोटी टहनियों जी तोड़ने पर दूध निकलता है जो लसलसा होता है ।

13. मीठा घास- यह बगान, खेतों के साथ पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे होते हैं और फल छोटे-छोटे होते हैं जो राइ के दाने के बराबर देखने में लगते हैं। स्वाद में मीठा होने के कारण मीठा घास के रूप में जाना जाता है ।

14. भुई आंवला- यह एक अत्यंत उपयोगी पौधा है जो बरसात के मौसम में जनमते हैं। इस पौधे की ऊंचाई 1- 25 इंच ऊँचा तथा कई शाखाओं वाले होते हैं। पत्तियां आकार में आंवले की पत्तियों की सी होती है और निचली सतह पर छोटे छोटे गोल फल पाए जाते हैं। यह जाड़े के आरंभ होते होते पक जाते हैं और फल तथा बीज पककर झड जाते हैं और पौधे समाप्त होते हैं ।

15. अड़हुल- अड़हुल का फूल लोगो के घरों में लगाया जाता है।यह दो प्रकार का होता है - लाल और सफ़ेद जो दवा के काम में लाया जाता है। अड़हुल का पत्ता गहरा हरा होता है।

16. घृतकुमारी/ घेंक्वार- यह एक से ढाई फूट ऊँचा प्रसिध्द पौधा है। इसकी ढाई से चार इंच चौड़ी,नुकीली एवं कांटेदार किनारों वाली पत्तियां अत्यंत मोटी एवं गूदेदार होती है पत्तियों में हरे छिलके के नीचे गाढ़ा, लसलसा रंगीन जेली के सामान रस भरा होता है जो दवा के रूप में उपयोग होता है ।

17. महुआ- महुआ का वृक्ष 40-50 फीट ऊँचा होता है। इसकी छाल कालापन लिए धूसर रंग की तथा अन्दर से लाल होती है।इसके पत्ते 5- 9 इंच चौड़े होते हैं। यह अंडाकार, आयताकार, शाखाओं के अग्र भाग पर समूह में होते हैं। महुआ के फूल सफ़ेद रसीले और मांसल होते हैं। इसमे मधुर गंध आती है। इसका पका फल मीठा तथा कच्चा में हरे रंग का तथा पकने पर पीला या नारंगी रंग का होता है ।

18. दूब घास- दूब घास 10 -40 सेंटी मीटर ऊँचा होता है। इसके पत्ते 2- 10 सेंटी मीटर लम्बे होते है इसके फूल और फल सालों भर पायी जाती है। दूब घास दो प्रकार के होते हैं - हरा और सफ़ेद हरी दूब को नीली या काली दूब भी कहते है

19. आंवला- इसका वृक्ष 5-10 मीटर ऊँचा होता है । आंवला स्वाद में कटु, तीखे, खट्टे, मधुर और कसैले होते हैं।अन्य फलों की अपेक्षा आंवले में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। उसके फूल पत्तीओं के नीचे गुच्छे के रूप में होती है। इनका रंग हल्का हरा तथा सुगन्धित होता है इसके छाल धूसर रंग के होते हैं। इसके छोटे पत्ते 10 - 13 सेंटी मीटर लम्बे टहनियों के सहारे लगा रहता है इसके फल फरवरी -मार्च में पाक कर तैयार हो जाते हैं जो हरापन लिए पिला रहता है ।

20. पीपल- पीपल विशाल वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएँ होती है।इनके पत्ते गहरे हरे रंग के हृदय आकार होती है। इनके जड़, फल, छाल, जटा, दूध सभी उपयोग में लाये जाते हैं। हमारे भारत में पीपल का धार्मिक महत्त्व है ।

21. लाजवंती/लजौली- लाजवंती नमी वाले स्थानों में जायदा पायी जाती है इसके छोटे पौधे में अनेक शाखाएं होती है। इनके पत्ते को छूने पर ये सिकुड़ कर आपस में सट जाती है। इस कारण इसी लजौली नाम से जाना जाता है इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं ।

22. करेला- यह साधारणतया व्यव्हार में लायी जाने वाली उपयोगी हरी सब्जी है जो लतेदार होती है। इसका रंग गहरा हरा तथा बीज सफ़ेद होता है। पकने पर फल का रंग पिला तथा बीज लाल होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है ।

23. पिपली- साधारणतया ये गरम मसले की सामग्री के रूप में जानी जाती है। पिपली की कोमल लताएँ 1-2 मीटर जमीन पर फैलती है ये गहरे हरे रंग के चिकने पत्ते 2-3 इंच लम्बे एवं 1-3 चौड़े हृदयाकार के होते हैं। इसके कच्चे फल पीले होते हैं तथा पकने पर गहरा हरा फिर काला हो जाता है। इसके फलों को ही पिपली कहते हैं ।

24. अमरुद- अमरुद एक फलदार वृक्ष है। यह साधारणतया लोगों के घर के आंगन में पाया जाता है इसका फल कच्चा में हरा और पकने पर पिला हो जाता है। प्रकार - यह सफ़ेद और गुलाबी गर्भ वाले होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। यह मीठा कसैला, शीतल स्वादिस्ट फल है जो आसानी से उपलब्ध होता है ।

25. कंटकारी/ रेंगनी- यह परती जमीन में पाए जाने वाला कांटेदार हलकी हरी जड़ी है। इसके कांटेदार पौधे 5- 10 सेंटी मीटर लम्बी होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके फल के भीतर असंख्य बीज पाए जाते हैं ।

26. जामुन- जामुन एक उत्तम फल है। गर्मी के दिनों में जैसा आम का महत्व है वैसे ही इसका महत्व गर्मी के अंत तथा बरसात में होता है। यह स्वाद में मीठा कुछ खट्टा कुछ कसैले होते हैं। जामुन कर रंग गहरा बैंगनी होता है ।

27. इमली- इमली एक बड़ा वृक्ष है जिसके पत्ते समूह में पाए जाते हैं जो आंवले के पत्ते की तरह छोटे होते हैं। इसका फल आरंभ में हरा पकने पर हल्का भूरा होता है यह स्वाद में खट्टा होता है।

28. अर्जुन- यह असंख्य शाखाओं वाला लम्बा वृक्ष है। इसके पत्ते एकदूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसके फूल समूह में पाए जाते हैं तथा फल गुठलीदार होता है जिसमें पांच और से पंख की तरह घेरे होते हैं ।

29. बहेड़ा- बहेड़ा का पेड़ 15- 125 फीट ऊँचा पाया जाता है, इसका तना गोल एवं आकार में लम्बा , 8 -35 फीट तक के घेरे वाला होता है। इसकी छाल तोड़ी कालिमा उक्त भूरी और खुरदुरी होती है।इसके फल, फूल, बीज, वृक्ष की छाल, पत्ते तथा लकड़ी सभी दवा के काम में आते हैं ।

30. हर्रे- यह एक बड़ा वृक्ष है। इसके फल कच्चे में हरे तथा पकने पर पीले धूमिल रंग के होते हैं। इसके फल शीत काल में लगते हैं जिसे जनवरी - अप्रैल में जमा किया जाता है। इसके छाल भूरे रंग के होते हैं। इसके फूल छोटे, पीताभ तथा फल 1-2 इंच लम्बे, अंडाकार होते हैं ।

31. मेथी- यह लोकप्रिय भाजिओं में से एक है। इनके गुणों के कारण इसका उपयोग प्रत्यक घर में होता है। इस पौधे की ऊंचाई 1-1 ड्ड फीट होती है, बिना शाखाओं के मेथी की भाजी तीखी, कडवी, और वायुनाशक है। छोटानागपुर में इसे सगों के साथ मिला कर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लौह तत्त्व की मात्रा अधिक होती है ।

32. सिन्दुआर/ निर्गुण्डी- यह झड़ी दार पौधा जो कभी कभी छोटा पेड़ का रूप ले लेता है। इसके पत्ते 5 -10 सेंटीमीटर लम्बी तथा छाल धूसर रंग का होता है इसके फूल बहुत छोटे और नीलेपन लिए बैंगनी रंग के होते हैं जो गुच्छे दार होते हैं

सेब के पेड़ की छँटाई कैसे करें

सहयोगी लेखक द्वारा Andrew Carberry, MPH

अपने घर के गार्डन में ही सेब का पेड़ उगाने की प्रोसेस और इसके बाद आने वाले फल, दोनों को ही देखकर मन को बहुत खुशी मिल सकती है। अगर आप एक सेब का पेड़ उगा रहे हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा फल पाना चाहते हैं, तो फिर शायद आपको पेड़ की छँटाई करने की जरूरत के बारे में भी मालूम ही होगा। पेड़ की छँटाई करने से पेड़ हेल्दी हो जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और समय के साथ उसमें पहले से ज्यादा और अच्छी क्वालिटी के फल भी उगना शुरू हो जाते हैं। अपने पेड़ को नजरअंदाज करके उसे अजीब शेप में न बढ़ते रहने दें, बल्कि आप खुद ही सेब के पेड़ की छँटाई करने की कोशिश करें।

अगर आपको जरूरत है, तो छँटाई को वसंत ऋतु के आखिर में और गर्मियों की शुरुआत में भी किया जा सकता है।

बारिश के दौरान पेड़ की छँटाई न करें, क्योंकि उसमें शायद नई ग्रोथ होना शुरू तो हो जाएगी, लेकिन ठंड के मौसम में वो रह नहीं पाएगी और खराब हो जाएगी।

सही टूल्स इकट्ठे करें अपने पेड़ के ऊपर कोई नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए छँटाई करने के लिए कुछ खास तरह के टूल की जरूरत पड़ती है। आप जिस भी ब्लेड से पेड़ की शाखाओं को काट रहे हैं, उसका साइज आपके द्वारा काटे जाने वाली शाखाओं के साइज के अनुपात में रहना चाहिए। छोटे हिस्सों के लिए, एक हैंड प्रूनर्स का इस्तेमाल करें। करीब 1 इंच तक बड़ी शाखाओं के लिए लोपर्स खासतौर से पेड़ की छँटाई के लिए बना एक कटिंग टूल) का इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 इंच से भी मोटी शाखाओं को काटने के लिए एक आरी (एक फोल्डिंग सॉ इस काम में बेहतर मदद करेगी) का इस्तेमाल करें।

तय करें कि आपको कितनी छँटाई करने की जरूरत हैं- एक अच्छी तरह से काटा हुआ हेल्दी एप्पल ट्री एक कम शेड या कम छाँव वाला पेड़ रहेगा, जिसकी शाखाओं के बीच में काफी जगह रहेगी।

अगर आपका सेब का पेड़ एक अच्छे शेड वाला या घना पेड़ है, तो निश्चित रूप से ये पेड़ छँटाई करने के लायक हो गया है। हालांकि, सभी पेड़ो की छँटाई नहीं की जानी चाहिए। जब तक कि आपका पेड़ कम से कम तीन साल पुराना नहीं हो जाता, तब तक

सकर्स को हटाएँ

सकर्स कुछ अनचाहे शूट्स (या तने) होते हैं, जो ट्रंक के बेस पर बढ़ते हैं। अपने पेड़ के ट्रंक के बेस पर उगे इन शूट्स को हटाकर पेड़ को एक अच्छा शेप दें। सकर्स अकेले ही पेड़ का वो भाग होते हैं, जिन्हें गर्मियों के आखिर में या बारिश की शुरुआत में भी काटा या हटाया जा सकता है।

के लिए उसकी छँटाई न करें। अगर पेड़ के काफी हिस्सों की छँटाई करने की जरूरत है, तो इस काम को अलग-अलग सीजन में बाँट लें।

पेड़ के एक मजबूत फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने और उसे शेप देना शुरू करने के लिए एक यंग या छोटे पेड़ की छँटाई की जाती है। बड़े या मेच्योर पेड़ की छँटाई से बड़े, हेल्दी फलों को बढ़ावा मिलता है और उसका ओवरऑल शेप भी बरकरार रहता है।[5]

एक सही शेप पाएँ आपके सेब के पेड़ को हल्का सा कोन जैसे शेप में रहना चाहिए, जिसमें ऊपर के मुक़ाबले नीचे की ओर ज्यादा वॉल्यूम रहनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी ज्यादा से ज्यादा शाखाओं पर धूप पहुँच पाएगी। इसके पहले की आप छँटाई करना शुरू करें, एक बात का ध्यान रखें कि आपको आपके पेड़ के ऊपर की शाखाओं पर एक पिरामिड के आकार का फ्रेमवर्क तैयार करना है।

अपने पेड़ की सबसे बड़ी शाखाओं को चुनें

एप्पल के पेड़ उनके बीच वाले ट्रंक या तने के साथ में जुड़ी शाखा के साथ में और फिर इनसे जुड़ी दूसरी स्केफ़ोल्ड ब्रांच (अगली सबसे बड़ी शाखाओं) के साथ में बढ़ा करते हैं। ऊपर से देखने पर, आपके पेड़ पर केवल कुछ ही ऐसी बड़ी शाखाएँ रहना चाहिए, जो एक-दूसरे को क्रॉस न करें और उनके बीच में एक-समान स्पेस छोड़ें। आपके पेड़ के साइज के आधार पर, उसमें केवल 2 से 6 प्राइमरी स्केफ़ोल्ड ब्रांचेस रहना चाहिए। बाकी की शाखाओं को हटा दिया जाना चाहिए।

इन स्केफ़ोल्ड ब्रांचेस का एंगल भी काफी जरूरी होता है। अच्छी स्केफ़ोल्ड ब्रांचेस उनके ट्रंक से कुछ 45 से 50 डिग्री के एंगल पर रहेंगी। अगर एंगल इससे छोटा है, तो वो शाखा शायद अपने फलों के भार से टूटकर अलग हो जाएगी। अगर एंगल इससे बड़ा हुआ, तो फिर उस पर ज्यादा फल नहीं रह सकेंगे।

एरियल व्यू (ऊपर से) देखे जाने पर, पेड़ के ऊपर मौजूद स्केफ़ोल्ड ब्रांचेस को एक स्टार की तरह या फिर एक व्हील के स्पोक की तरह दिखाई देना चाहिए।

खराब हुई लकड़ी को काटें

पेड़ पर मौजूद उन सभी डैड, बीमारीग्रस्त या डैमेज हुई लकड़ियों को काटकर अलग करें, जो पपड़ी बनकर उखड़ रही है या फिर जिसका रंग उड़ा हुआ है। आप चाहें तो इस तरह की डैड, डैमेज या बीमारीग्रस्त लकड़ी को सालभर में किसी भी समय पर भी हटाया जा सकता है और आपको इन्हें देखते ही इन्हें हटा देना चाहिए। अगर शाखा पर कोई भी फल नहीं है, तो उसे पूरा काटकर अलग कर दें। अगर उस पर शाखा के बेस की ओर फल हैं, तो फिर ठीक बाहर की ओर फेस किए फल के ऊपर तक की कटाई करें। हर एक कट को इस तरह से एंगल करें, ताकि बारिश का पानी पेड़ के ऊपर जमा होकर और उसे सड़ाने की बजाय, सीधे नीचे बह सके।

नीचे की ओर बढ़ने वाली शाखाओं को काटें अगर आपके सेब के पेड़ के ऊपर ऐसी कोई भी शाखा है, जो नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो उसे हटाया जाना चाहिए। ये बड़े और हेल्दी फलों को नहीं सह सकेगी और ये उन जरूरी स्पेस और धूप को भी रोक लेगा, जिसे बाकी की दूसरी शाखाएँ शायद ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती थीं।

बची हुई शाखाओं की छँटाई करें बाकी की शाखाओं को उनकी लंबाई के करीब एक-तिहाई हिस्से में काटकर तने को मोटा होने और आने वाले सीजन में उस पर फूल उगाने के लिए एंकरेज करें। हेल्दी शेप को बढ़ावा देने के लिए ठीक एक बाहर की ओर फेस किए बड्स के ऊपर से काटें।

सलाह

कभी भी अपने पेड़ की एक-तिहाई ग्रोथ से ज्यादा की कटिंग न करें।

सभी कटी हुई शाखाओं को हटाएँ और जहां भी हो सके, कम्पोस्ट करें या फिर उन्हें मल्च क्लिपिंग्स) की तरह तैयार करें।

चीजें जिनकी आपको आवश्यकता होगी

प्रूनिंग सॉ या लोपर्स

ऊंची शाखाओं के लिए टेलीस्कोपिक प्रूनर

अगर रखना चाहें, तो गार्डन ग्लव्स

एक-साथ गुच्छे में हुई बढ़त की छँटाई करें

इस तरह की ग्रोथ खासतौर से मेच्योर पेड़ों में होना कॉमन हैं, इस तरह के गुच्छे में पेड़ की एक ही लोकेशन से तीन या और भी ज्यादा छोटी-छोटी शाखाएँ निकल रही होती हैं। क्योंकि इसमें एक ही जगह से इतने सारे ब्रांचेस बढ़ रहे होते हैं, इसलिए ये शाखाएँ बढ़ने पर कमजोर होती और दूसरी ब्रांच को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। निर्धारित करें कि कौन सा सबसे बड़ा और हेल्दी गुच्छा है और फिर व्होर्ल में से बचे हुए ब्रांचेस को काटकर अलग कर दें।

छँटाई करने की जरूरत को समझें

जैसे ही आपको ये महसूस हो जाए कि आपके सेब के पेड़ को छँटाई करने की जरूरत है, तब आपके मन में तुरंत ही उठने और जल्दी से अपने पेड़ की शाखाओं को काटने का ख्याल आ सकता है। हालांकि, अपने पेड़ को बर्बाद करने से बचने के लिए जरूरी है कि आप उसे एक सही टाइम पर ही काटें। वसंत ऋतु के पहले या दूसरे शुरुआती महीने में, शीत ऋतु के कम से कम से हफ्ते बाद छँटाई करें।